[Hindi]

रेल मंत्रालय / डीएफसीसीआईएल

बडोदरा–जेएनपीटी एवं रेवाड़ी–दादरी के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना (द्वितीय चरण) के लिए पुनर्वास और पुनः स्थापना योजना

(आर आर पी)

नवम्बर – 2011

कार्यकारिणी सारांश

परियोजना–एक नजर में

रेल मंत्रालय दो महानगरों दिल्ली और मुंबई और उनके अपने राज्यों के बीच कम यातायात लागत और कम समय में बिना किसी बाधा के बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं के शीघ्र और सरल यातायात के लिए एक बहु आयामी उच्च एक्सल लदान डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 37.7 मि.टन के माल भाड़ा लदान के लिए इसे तैयार किया गया है जो अगले 10 वर्षों में 140.4 मि.टन तक बढ़ जाएगा। परियोजना अभी नियोजन स्तर पर है। इसे 2006 में शुरू किया गया था और 2012 में पूरा होगा। निर्माण कार्य 4–5 वर्षों में वर्ष 2012 से 2016 के बीच में पूरी करने की योजना है वाणिज्यिक यातायात दिसम्बर 2016 से शुरू होने की योजना है।

सामान्य विशेषताएं

- कोरीडोर की लंबाई: 585 कि.मी.
- बडोदरा–मुम्बई सेक्शन की लम्बाई– 420 कि.मी.
- रेवाड़ी–दादरी सेक्शन की लम्बाई– 145 कि.मी.
- जंक्शन स्टेशन: 6, क्रासिंग स्टेशन– 11
- प्रमुख एवं महत्वपूर्ण पुलों की संख्या– 165
  आर ओ बी की संख्या– 77
- जहां से संरेखण गुजरेगा: महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली।
  - शामिल जिले: 14
  - शामिल गाँव: 374
- रास्ते की चौड़ाई: समानांतर सेक्शन में लगभग 35 मी., घुमावदार सेक्शन में 60 मी.
- अधिकतम गति: 100 कि.मी. प्रति घंटा

परियोजना के लाभ

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण के साथ–साथ भारत में अर्थव्यवस्था की वर्तमान दर को बढ़ाने में मदद करना है:

- भारत में मालभाड़ा यातायात के सुधार के कारण राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास को तेज करना।
- डीएफसी के साथ औद्योगिक विकास के बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगें।
- डीएफसी द्वारा दूरी और गति के आधार पर वन और मत्स्य विभाग के साथ–साथ क्षेत्र में किसानों के लिए बाजार का विस्तार और सुधार होगा। जिससे कृषि उत्पादन के यातायातायन में सुधार होगा।
- ट्रक द्वारा यातायात की तुला में वस्तुओं के यातायात के लिए कम उर्जा का उपयोग।
- डीएफसी संरेखण के साथ स्थानीय समुदाय के कारण कोई उत्सर्जन नहीं (सड़क द्वारा ट्रक से गैसियस उत्सर्जन की कमी)

पश्चिमी कोरीडोर में डीएफसी परियोजना (द्वितीय चरण) का भूमि अधिग्रहण पैटर्न

डीएफसी रेखांकन वडोदरा–सूरत–बसई–जेएनपीटी और रेवाड़ी–दादरी से होकर गुजरता है। भूमि के अधिग्रहण और पुनः स्थापना का रेखीय पैटर्न परियोजना अभिकल्प के लिए अपेक्षित होगा। स्थायी प्रकार के ढांचे, स्थानीय समुदाय, शहरी नियोजन क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र, परियोजना के साथ बने बसे हुए शहरी क्षेत्र में अभ्यारण आदि को बचाने या नुकसान को कम से कम करने के लिए चक्करदार रेखांकन पर विचार किया गया है। मूल रूप से कुछ जगहों पर रेखांकन वर्तमान रेलवे लाइन के समान्तर है। जबकि सूरत, धानु, बसई, कुन्दे बहार और रेवाड़ी–दादरी में वह चक्कादार है, दोनों ही स्थितियों समानांतर और घुमावदार सेक्शनों में कुछ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

(D) निष्पादन एजेन्सी (EA)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

डीएफसी परियोजना के लिए आधारभूत विधान और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनः स्थापना

- **रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008**

  ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत डीएफसी परियोजना (जिसे विशेष रेलवे परियोजना के रूप में घोषित किया गया है) द्वारा भूमि अधिगृहित की जा रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 लागू नहीं हैं।
- **राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति, 2007**

  डीएफसी परियोजना के लिए बहुत कम भूमि की आवश्यकता है। रेलवे परियोजना के लिए रेखीय भूमि अधिग्रहण पर एनआरआरपी 2007 का पैरा 7.19 मूल रूप से डीएफसी परियोजना के लिए लागू है।
- **सक्षम प्राधिकारी**

  ऐसा व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के लिए, जो डीएफसी परियोजना के लिए विशेष रूप से उल्लिखित हों, के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया हो।

आर ए ए 2008 के अनुसार इच्छुक व्यक्ति

1.इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले सभी व्यक्ति।
2.आदिवासी और अन्य वनवासी जो अनु.ज.जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपने पारंपरिक अधिकारी खो चुके हैं।
3.ऐसा व्यक्ति जो भूमि की सुविधा से प्रभावित हो
4.ऐसे व्यक्ति जो राज्य के नियमों के अंतर्गत किराये का अधिकार रखते हों।

अंतिम तारीख

आर ए ए 2008, एनआरआरपी 2007 के अनुसार पात्रता के लिए अंतिम तारीख है:–

i) अंतिम उपाधिधारियों एवं गैर उपाधिधारियों के लिए वह तारीख जब आर एए 2008 की धारा 20 ए के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमित की गई हो।

पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति

पुनः स्थापना और पुनर्वास नीति उन सिद्धांतों पर आधारित है कि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति परियोजना से पहले की उनकी स्थिति से अच्छी हो।

नीति के अनुसार आरआरपी के उद्देश्य

- परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति परियोजना के कारण उनकी पहले की स्थिति से बदतर नहीं होगी।
- सभी व्यवहार्य विकल्पों को अपनाकर भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनः स्थापना प्रभावों को बचाना या कम से कम करना।
- पुनर्वास पैकेज की पर्याप्तता सुनिश्चित करना और प्रभावित परिवारों के सक्रिय सहयोग से पुनर्वास प्रक्रिया के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- अनु.जा./अनु.ज.जा./महिलाओं, बुजुर्गों, एवं विकलांगों/असुरक्षित समूहों जैसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष देख–भाल
- बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना और पीएपीज के भरण–पोषण के लिए आय प्रदान करना।
- अपेक्षित निकाय और प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना।
- भूमि को लेने और उस पर किसी प्रकार की निर्माण गतिविधि आरंभ करने से पूर्व क्षतिपूर्ति और पुनः स्थापना सहायता के भुगतान को सुनिश्चित करना।

मौलिक क्षतिपूर्ति नीति

- भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी की होगी।
- मूलरूप से क्षतिपूर्ति की राशि भूमि खोने वाले व्यक्ति को आर एए 2008 के अनुसार दी जाएगी। आर एए 2008 के अनुसार बाजार दर निर्धारित की जाएगी और भूमि की बाजार दर के अलावा हर मामले में अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बाजार कीमत की 60 प्रतिशत राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी (सेक्शन 20एफ(9), आरआरए 2008)। अन्यथा, राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए मंजूर दर को सक्षम प्राधिकारी आर एए 2008 के अनुसार अपना सकते है।
- भूमि में इच्छुक कोई व्यक्ति भूमि अधिग्रहण के इरादे की घोषणा के लिए अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर भूमि अधिग्रहण के लिए आपत्ति प्रकट कर सकता है (सेक्शन 20डी(1).आरआरए 2008)।
- भवन और अन्य अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियां, वृक्ष, पौधे और उस भूमि या भवन पर खड़ी फसल जिसे अधिगृहित किया जाना है, की बाजार कीमत का निर्धारण उस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा (सेक्शन 20 जी (4,5,6), आरआरए 2008)।
- क्षतिपूर्ति राशि सामान्यतः भूमि अधिग्रहण की घोषणा की अधिसूचना के एक वर्ष के अंदर दे दी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितयों में इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाई गई स्थिति में एक ईनाम भी दिया जाता है। अधिकृत व्यक्तियों को ईनाम में देरी के कारण ऐसे विलंब के प्रत्येक माह की उस अवधि के लिए एक अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाएगी सेक्शन 20 एफ (1,2),आरआरए 2008)
- क्षतिपूर्ति लेने के लिए नोटिस के एक वर्ष बाद तक यदि इच्छुक व्यक्ति क्षतिपूर्ति राशि के लिए दावा नहीं करता है तो ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति राशि ईए के पास एक अलग खाते में परियोजना के अंत तक रख दी जाएगी। इच्छुक पार्टियां अपनी क्षतिपूर्ति का दावा या तो स्वयं या अपने वैध उत्तराधिकारी के माध्यम से संतोषजनक सत्यापन के बाद कर सकती हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में से कुछ भी लागू नहीं होगा।
- रेलवे लाइनों जैसे रेखीय अधिग्रहण के मामले में, जहां परियोजना के उद्देश्य के लिए बहुत कम भूमि अर्जित की जाती है या रास्ते का उपयोग किया जाता है, प्रभावित परिवार में प्रत्येक खातेदार को अपेक्षित निकाय द्वारा एक इतनी अनुदान राशि के भुगतान की पेशकश की जाएगी जितनी उपयुक्त सरकार द्वारा तय हो किंतु 20000/–रू. से कम न हो। क्षतिपूर्ति के अलावा या अधिनियम के अंतर्गत देय कोई अन्य लाभ या कार्यक्रम या योजना जिसके अंतर्गत भूमि, घर या अन्य सम्पत्ति अर्जित की जाती है (एनआरआरपी 2007)।

पीएपीज के मामले में जो भूमिहीन कर दिये जाते हैं या भूमि अधिग्रहण के कारण उनकी स्थिति छोटे या सीमांत किसान तक सीमित कर दी जाती है तो वे 750 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर पुनर्वास सहायता पाने के हकदार होंगे।

परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनःस्थापना के लिए सामान्य सिद्धान्त

- परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/परिवार (पीएपीज/पीएएफस) को उपाधिकारी, गैर उपाधिधारी, किओस्क, वेंडर्स आदि में कोटिकृत किया जाएगा।
- विभिन्न श्रेणियों के पीएपीज के लिए मौलिक पात्रता (इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स) के अनुसार क्षतिपूर्ति और सहायता दी जाएगी।
- पीएपीज का उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए परियोजना लागत पर सहायता दी जाएगी।
- मौलिक पात्रता(इनटाइटलमेंट मेट्रिक्स) के अनुसार असुरक्षित पीएपीज को पुनर्वास और पुनः स्थापना के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- पीएपीज अपनी खोई हुई सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति स्थानापन्न लागत पर प्राप्त करेंगे।
- अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद यदि कोई परियोजना क्षेत्र में आता है तो वह सहायता का हकदार नहीं होगा।
- परियोजना का अलग पुनः स्थापना बजट होगा।
- पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति, न्यूनीकरण उपाय, पुनः स्थापना योजना तैयारी और कार्यान्वयन से संबंधित समस्त प्रकार की सूचना पीएपीज सहित सभी स्टेक होल्डर्रों को दी जाएगी।
- अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए परियोजना केक विभिन्न स्तरों पर स्टेक होल्डरों के साथ लोक परामर्श बैठक आयोजित की जाएगी।
- झगड़ों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त शिकायत निपटान तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- स्टेक होल्डरों और पीएपीज के साथ हुई बातचीत को दर्ज किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अर्थपूर्ण बातचीत पुनर्वास और पुनःस्थापना योजना के दौरान भी जारी रहेगी।
- अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद उपाधिधारक/टेनेंसी की स्थिति में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्षतिपूर्ति, सहायता और पुनर्वास के लिए पात्रता

- पात्रता के लिए अंतिम तारीख वह तारीख है जिस पर प्रभावित क्षेत्र में वैध मालिकों और गैर उपाधिधारकों के लिए आरएए 2008 की धारा 20 ए के अंतर्गत निर्धारित अधिसूचना के अनुसार अधिसूचना जारी की जाती है।
- पीएपीज की विभिन्न श्रेणियों के पात्रता नीचे अनुवर्ती में दिखाए गए मौलिक पात्रता के अनुसार होगी।
- पात्रता की इकाई परिवार होगी।
- उपाधिधारक पीएपीज सहायता के साथ–साथ क्षतिपूर्ति के लिए भी पात्र होगा
- गैर उपाधिधारक पीएपीज उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। फिर भी भूमि पर किए गए निवेश जैसे ढांचों और अन्य संपत्तियों के स्थानापन्न कीमत के अनुसार क्षतिपूर्ति मिलेगी (इनटाइटिलमेन्ट मैट्रिक्स के नोट डी व नोट एफ के अनुसार)। वे पुनः स्थापना नीति और मौलिक पात्रता के अनुसार आर एवं आर सहायता के लिए भी पात्र होंगे।
- गणना के दौरान न गिने गए पीएपीज के मामले में प्रभावित क्षेत्र में अंतिम तारीख से पहले उसकी उपस्थिति को कोई साक्ष्य सिद्ध करता है तो शिकायत निपटान समिति द्वारा उचित सत्यापन के बाद उसे पीएपीज की सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
- असुरक्षित समूहों के पीएपीज मौलिक पात्रता में निर्दिष्ट अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र होंगे।
- पीएपीज ढहाई गई सामग्री के अवशेष को बिना किसी लागत के परियोजना गतिविधियों में बिना किसी देरी के ले जा सकेगा।
- बेदखली के लिए यदि कोई नोटिस किसी व्यक्ति/परिवार को अंतिम तारीख से पहले दिया गया है और मामला न्यायालय में लंबित है तो ऐसी स्थिति में पीएपीज की पात्रता न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति के अनुसार की जाएगी और आर आर पी के प्रावधानों के अनुसार पीएपीज क्षतिपूर्ति/सहायता के लिए पात्र होगा।

आरएए 2008 और एनआरआरपी 2007 पर आधारित डीएफसीसी परियोजना के लिए मौलिक पात्रता

(इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स)

क्रम संख्या	आवेदन	प्रभावित व्यक्तियों की परिभाषा	हकदारी	विवरण
(क) निजी कृषि, रिहायशी और वाणिज्यिक भूमि की हानि				
1	परियोजना के रास्ते में आने वाली भूमि	पारम्परिक भूमि अधिकारों सहित वैध शीर्षक धारक और प्रभावित पार्टियां	1. स्थानापन्न लागत पर क्षतिपूर्ति 2. पुनः स्थानापन्न और पुनर्वास	(i) उस भूमि के लिए बाजार मूल्य पर नकद क्षतिपूर्ति जो नोट (क) (आर ए ए 2008 की धारा 20 जी) में उल्लिखित अनुसार निर्धारित की जाएगी। (ii) उपर्युक्त (1) आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (9) में निर्धारित क्षतिपूर्ति पर 60 प्रतिशत मुआवजा (iii) ऐसी स्थिति में जहाँ कि राज्य सरकार द्वारा कोई एक्ट या गजट नोटिफिकेशन या अन्य कोई भूमि मुआवजे के उद्देश्य से दर निर्धारण की मंजूरी की गई हो, सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त (i) एवं (ii) के बदले में उसे भी अपना सकते हैं। (iv) 1500 वर्ग मीटर तक की अधिग्रहित भूमि के लिए 20000/– एवं उससे ऊपर की अधिग्रहित भूमि हेतु 15 रू0 प्रति वर्ग की दर से अतिरिक्त अनुदान राशि देय होगी। (एन आर आर पी पैरा 7.19) (v) भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप यदि भूमि धारक भूमि हीन हो जाता है या उसकी स्थिति 'छोटे' या 'सीमांत' किसान की हो जाती है तो उसे 750 दिन के बराबर न्यूनतम कृषि मजदूरी की पुनर्वास सहायता दी जाएगी। (vi) संदेह/झगड़े के मामले में सक्षम प्राधिकारी मुआवजे की राशि निर्धारित करने से पूर्व एक स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ता से मदद ले सकता है। इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया नोट बी में है। (vii) अधिग्रहण/अवशेष भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की नीति नोट सी के अनुसार होगी। (viii) स्टैंड ड्यूटी का रिफंड और स्थानापन्न भूमि के लिए लगाए गए पंजीकरण प्रभार परियोजना द्वारा दिये जाएंगे। स्थानापन्न भूमि, आर ए ए, 2008 की धारा (एच) के अनुसार प्रभावित पार्टी को दिए गए क्षतिपूर्ति के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के अंदर खरीद ली जाएंगी।
2		पंजीकृत किरायेदारों, ठेकेदारों और पट्टे धारक	खड़ी फसल के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति	पंजीकृत किरायेदार ठेकेदार और पट्टेधारक भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए योग्य नहीं है। वे बाजार दर पर अधिम क्षतिपूर्ति के लिए तभी योग्य होंगें जब ई ए द्वारा 3 माह पूर्व नोटिस नहीं दिया गया हो।

3		अपंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतीहार, पट्टे धारक, शेयर कोपर्स	खड़ी फसल के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति	अपंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतीहर, पट्टे धारक और शेयर कोपर्स भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए योग्य नहीं है। वे बाजार दर पर खड़ी फसल की क्षतिपूर्ति के लिए तभी योग्य है जब इन्हें ई ए द्वारा 3 माह पूर्व अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। शेयर कोपर्स के मामले में क्षतिपूर्ति भू स्वामी और शेयर कोपर्स के बीच आपसी समझौते के अनुपात में होगी।
(ख) निजी ढांचे की हानि (रिहायशी) वाणिज्यिक				
4	परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा	शीर्षक धारक/मालिक	स्थानापन्न दर पर क्षतिपूर्ति पुनः स्थानापन्न और पुनर्वास सहायता	(i) स्थानापन्न लागत पर उस ढांचे के लिए नकद क्षतिपूर्ति जो नोट डी के अनुसार निर्धारित की जाएगी (ii) ढहाए गए ढांचों से प्राप्त बची हुई सामग्री का अधिकार (iii) ढांचों को खाली कराने के लिए तीन माह का नोटिस (iv) उपर्युक्त (i) में निर्धारित किए गए बाजार मूल्य पर प्रिवेलिंग दरों पर नए वैकल्पिक घरों/दुकानों की खरीद के लिए स्टंप ड्यूटी और पंजीकरण प्रभार का रिफंड। वैकल्पिक घरों/दुकानों में धारा 20 (एच), आर ए ए 2008 के अनुसार प्रभावित पार्टी को किए गए क्षतिपूर्ति के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के अंदर खरीद की जाएगी। (v) पुनः स्थापना और पुनर्वास सहायता निम्नानुसार लागू होगी:– (क) 4000/– रूपए प्रति परिवार

				पारगमन भत्ता (ख) प्रत्येक प्रभावित को विस्थापित होने पर 10000/– रूपए की एकमुश्त राशि स्थानान्तरण भत्ते के रूप में दी जाएगी (एन आर आर पी 2007 पैरा 7.10)। (ग) प्रत्येक परिवार को जिसके पास पशु हैं, के विस्थापित होने पर उसे पशु के शैड के निर्माण के लिए 15000/– रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। (एन आर आर पी पैरा 7.10, 2007)। (घ) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जो एक ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्व रोजगार व्यक्ति है के विस्थापित होने पर उसे वर्किंग शैड या दुकान के निर्माण के लिए 25000/– रूपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। (एन आर आर पी पैरा 7.12, 2007)। (ङ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को घर बनाने की सहायता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्तमान लागत के समकक्ष एवं शहरी क्षेत्रों में जे एन यू आर एम के अन्तर्गत लागत के समकक्ष
5	परियोजना के रास्ते में आने वाला ढांचा	किराएदार/पट्टे धारक	पुनः स्थापना और पुनर्वास सहायता	(i) पंजीकृत पट्टे धारी स्थानीय कानून के अनुसार ढांचा मालिक को देय क्षतिपूर्ति के विभाजन का हकदार होगा। (ii) किरायेदार के मामले में 10000/– रूपए की राशि स्थानान्तरण भत्ते के सहित तीन माह का लिखित नोटिस भी देना

				होगा। (एन आर आर पी 7.11) (iii) ढांचे को खाली करनो के लिए 3 माह का नोटिस। नोटिस न दिए जाने के मामले में तब नोटिस के स्थान पर तीन महीने का किराया भत्ता दिया जाएगा।
(ग) वृक्षों और फसलों की हानि				
6	परियोजना के रास्तें में खड़े वृक्ष, फसल	भू-स्वामी और हिताधिकारी	बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति	(i) फलों, खड़ी फसल को काटने और वृक्षों को हटाने के लिए प्रभावित पार्टियों को 3 माह का अग्रिम नोटिस (ii) द्वारा प्राकल्लित दर पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। (क) लकड़ी वृक्षों के लिए वन विभाग (ख) फसलों के लिए राज्य कृषि विस्तार विभाग (ग) पेरेनियल वृक्षों के लिए बागवानी विभाग (घ) वृक्षों, फसलों और पेरेनियल की हानि के लिए बाजार मूल्य पर अनौपचारिक सैटलर्स/स्क्वैटर्स सहित शीर्षक धारक और गैर शीर्षक धारकों को नकद सहायता।
(घ) आवासीय/वाणिज्यिक ढाँचों की क्षति (गैर शीर्षक धारकों द्वारा)				
7	परियोजना के रास्ते में आने वाले ढाँचे	20 ए के नोटिफिकेशन की तारीख तक ढाँचे का मालिक	स्थानापन्न लागत पर क्षतिपूर्ति पुनः स्थापना एवं पुनर्वास सहायता	(i) कब्जेदारों (जैसा कि नोट एफ में परिभाषित है) को खाली करने के लिए 3 माह की नोटिस देनी होगी या फसल/ढाँचे की हानि हेतु क्षतिपूर्ति देय होगी यदि नोटिस नहीं दी गई हो। विशिष्ट लोगों (स्क्वैटर्स) को (जैसा कि नोट एफ में परिभाषित है) नकद सहायता स्थानापन्न लागत पर जो कि नोट डी के अनुसार निर्धारित होगा, देय होगा। (ii) पुनः स्थापना एवं पुनर्वास सहायता इस प्रकार देय होगी– (क) प्रत्येक परिवार को रू0-4000/– परागमन भत्ता के रूप में। (ख) स्थानान्तरण भत्ता रू0-10000/– प्रत्येक परिवार को (पैरा 7.11 एन आर आर पी 2007) (ग) रू0-1500/– की सहायता पशुशाला की क्षतिपूर्ति हेतु (घ) यदि प्रभावित पार्टी ग्रामीण कारीगर, छोटा व्यापारी या स्वरोजगार व्यक्ति है, रू0 25000/– की सहायता, वर्किंग शेड/दुकान बनाने हेतु (ङ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को घर बनाने की सहायता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्तमान लागत के समकक्ष एवं शहरी क्षेत्रों में जे0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत लागत के समकक्ष
(ङ) आजीविका की हानि				
8	परियोजना के रास्ते में रहने वाले परिवार	शीर्षधारक/गैर शीर्ष धारक/बंटाईदार/कृषि मजदूर और कर्मचारी	पुनर्वास सहायता	(i) पुनर्वास सहायता 750 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के समतुल्य उन परिवारों को जिन्होंने अपनी आजीविका गवाँ दी है (एम आर आर पी पैरा-7.14) परन्तु ऐसे भू

				स्वामी जिन्होंने उपरोक्त सेक्शन 1(v) के अन्तर्गत 750 दिनों के बराबर न्यूनतम मजदूरी की सहायता का लाभ लेंगे, इस सहायता के पात्र नहीं होंगे। (ii) प्रत्येक परिवार को रू0 4000/– प्रशिक्षण सहायता आमदनी अर्जित करने हेतु (iii) परियोजना ठेकेदार द्वारा निर्माण के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को (विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को) अस्थायी रोजगार
(च) वलनरेबल ग्रुप (जैसा कि नोट ङ में परिभाषित किया गया है) और गरीबी रेखा से नीचे वालों को अतिरिक्त सहायता				
9	रास्ते में आने वाले प्रभावित परिवार	रास्ते में आने वाले प्रभावित परिवार	पुनः स्थापना और पुनर्वास सहायता	न्यूनतम मजदूरी के 300 दिनों के बराबर एक मुश्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता
(च2) अनु. ज. जाति के प्रभावित परिवारों की अतिरिक्त सहायता				
10	प्रभावित अनु0 जन जाति	रास्ते में आने वाले प्रभावित परिवार	पुनर्वास सहायता	(i) प्रचलित अधिकार या वन उत्पादक उपयोग की हानि के लिए प्रत्येक अनु.ज. जाति के प्रभावित परिवार को न्यूनतम कृषि मजदूर के 500 दिनों के बराबर एक अतिरिक्त एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएंगी। (पैरा 7.21.5 एन आर आर पी 2007) (ii) भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रत्येक अनु.जन जाति के प्रभावित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि की कम से कम एक तिहाई राशि प्रथम किश्त के रूप में प्रारंभ में

				दी जाएगी जबकि शेष राशि भूमि के कब्जे के समय दी जाएगी। (पैरा 7.21.4 एन आर आर पी 2007)
(छ) सामुदायिक अवसंरचना/सामुहिक संपत्ति संसाधनों की हानि				
11	रास्तें में ढांचे और अन्य संसाधन (जैसे भूमि,पानी,सामाजिक सेवाओं की पहुँच आदि)	प्रभावित समुदाय और समूह	सामुदायिक ढांचे और सामूहिक संपत्ति संसाधनों का पुनः निर्माण	समुदाय से परामर्श करके जो भी उचित हो सामुदायिक ढांचे का पुनः निर्माण और सामूहिक संपत्ति संसाधनों का स्थानापन्न
(ज) निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव				
12	निर्माण के दौरान स्थायी रूप से प्रभावित भूमि और संपत्तियाँ	भूमि और संपत्तियों के स्वामी	निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव के लिए क्षतिपूर्ति जैसे सामान्य यातायात का विघटन, भारी मशीनरी और प्लांट स्थल के संचलन के कारण भूमि संपत्तियों के समीपवर्ती पार्सल के कारण नुकसान	निर्माण के दौरान मशीनरी के संचलन या निर्माण प्लांट की स्थापना के कारण ढांचे या भूमि पर किसी प्रभाव की क्षतिपूर्ति लागत को ठेकेदार स्वयं वहन करेगा। प्रस्तावित रास्ते के बाहर पड़ने वाली भूमि के समस्त अस्थायी उपयोग के लिए भू. स्वामी और ठेकेदार के बीच लिखित अनुमोदन होना चाहिए। ठेकेदारों द्वारा निर्माण स्थलों की स्थापना डीएफसीसीआईएल से परामर्श करके की जाएगी।

नोट क

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति का निर्धारण आर एए 2008, धारा 20 जी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जो भूमि की बाजार दर का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मापदंड का उल्लेख करता है:–

(i) न्यूनतम भूमि दर, यदि कोई हो, क्षेत्र में बिक्री कार्यों के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 में उल्लिखित, जहां भूमि स्थित हो, या

(ii) गांव या आस पास के क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए बिक्री मूल्य का औसत, तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत बिक्रीनामों के 50 प्रतिशत से कम न हो, जहां उच्च कीमत दी गई है, जो अधिक हो।

2. जहां कहीं उपर्युक्त प्रावधान लागू न हों, संबंधित राज्य सरकार उक्त भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र की फ्लोर कीमत का आस पास के क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए दिए गए औसत उच्च मीमतों के आधार पर उल्लेख करेगी जो पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजीकृत बिक्रीनामों के 50 प्रतिशत से कम न हो जहां उच्च कीमत दी गई हो और सक्षम प्राधिकारी तदनुसार भूमि के मूल्य की गणना करे (आर ए ए 2008 की धारा 20 जी का अनुपालन किया जाएगा)

3. क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करते समय सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (8) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखेगा।

(i) भूमि का कब्जा लेते समय इच्छुक व्यक्तियों द्वारा यदि कोई नुकसान किया गया है जिसका कारण ऐसी भूमि का अन्य भूमि से कठिनता का दिया गया हो

(ii) भूमि का कब्जा लेते समय इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कोई नुकसान किया गया है जिस कारण अधिग्रहण उसकी अन्य अचल सम्पत्ति या उसकी आय को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता हो

(iii) यदि भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप इच्छुक व्यक्ति को उसका निवास या व्यापार स्थल बदलने के लिए दबाव डाला जाता है तो इस संबंध में होने वाले खर्च, यदि कोई है तो ऐसे परिवर्तन के लिए व प्रासंगिक होंगे।

4. अधिगृहीत की जा रही भूमि के बाजार मूल्य का मूल्यांकन और निर्धारण करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित करेगा :-

(i) ऐसी भूमि की नियत भूमि के प्रयोग की श्रेणी को जान लेना और

(ii) समीपवर्ती क्षेत्रों या आस पड़ोस में भूमि की नियत श्रेणी के मूल्य को जान लेना।

5. प्रयोगकर्ता के अधिकार के मामले में या किसी दूसरे की सम्पत्ति पर अधिकार की प्रकृति में यदि कोई भूमि अधिगृहीत की जाती है तो आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (1) के अंतर्गत निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि के 10 प्रतिशत की राशि का भुगतान ई ए द्वारा मालिक और अन्य दूसरे व्यक्ति को जिसका भूमि के प्रयोग का अधिकार प्रभावित होता हो, को किया जाएगा।

नोट 'ख'

डीएफसीसीआईएल सरकार के साथ पंजीकृत एक स्वतंत्र मूल्यांकन कर्त्ता को रखेगी जो निम्नानुसार स्थापना लागत का मूल्यांकन करने के लिए सहायता कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी तथ्य उपलब्ध करा सकता है:

(i) हाल ही में बिक्री किए गए और हस्तांतरण किए गए आगम पत्रों का मूल्यांकन करना और गांव या शहरी क्षेत्र और आस पड़ोस में उसी तरह की भूमि के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(ii) जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्कल रेट को तय करना।

(iii) भूमि के लिए कृषि उत्पादकता दर तय करना – 20 वर्षों के लिए।

भूमि के लिए क्षतिपूर्ति तय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो स्वतंत्र मूल्यांकन से तथ्य ले सकता है।

नोट 'ग'

यदि शेष बचे हुए प्लाट (प्लाटों) एक्नोमिकली जीने के योग्य नहीं है तो ई. ए. राज्य में लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा और तदनुसार क्षतिपूर्ति करेगा, यदि ई.ए. की खरीद के बाद जिले में मौजूद भूमि के औसत से शेष बची हुई भूमि कम है तो इस संबंध में वहां राज्य के नियम और विनियम स्पष्ट नहीं है तो प्रभावित पार्टी से करार करते समय ई.ए. निम्नलिखित में से एक का अनुपालन करेगा :

(i) ई.ए. इनटाइटलमैंट मैट्रिक्स में सूचीबद्ध इनटाइटलमैंट मैट्रिक्स का अनुपालन करते हुए परियोजना के लिए शेष भूमि की खरीद करेगा : या

(ii) ई.ए. भूमि की क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत प्रभावित पार्टी को उस जमीन के लिए देगा जो खरीदी नहीं गई हो।

नोट 'घ'

घरों, भवनों और अन्य अचल संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण बिना मूल्य ह्रास के आधार सूची दर का उल्लेख करते हुए स्थानापन्न लागत के आधार पर किया जाएगा। आधार सूची दर का विचार करते समय सरकार के साथ पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकन क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण इलाकों में रिहायशी और वाणिज्यिक ढांचों के लिए नवीनतम आधार सूची दर और मालिकों से परामर्श करके प्रयोग करेगा।

नोट 'ङ'

एन आर आर पी 2007 वल्नेबरल व्यक्तियों को अयोग्य, निराश्रय, अनाथ, विधवा, अविवाहित लड़कियों, परित्यक्ता स्त्री या ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, जिन्हें वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं है और जो कहीं भी परिवार के हिस्से के रूप में कवर नहीं होते है, को परिभाषित किया गया है। (पैरा 6.4 (v) एन आर आर पी 2007)

नोट 'च'

सीमांत किसान

ऐसा खेतीहर जिसके पास एक हैक्टेयर तक असिंचित भूमि हो या आधे हैक्टेयर तक सिंचित हो।

छोटा किसान

ऐसा खेतीहर जिसके पास दो हैक्टेयर तक असिंचित भूमि है या एक हैक्टेयर तक सिंचित भूमि हों, किन्तु सीमांत किसान से अधिक हो।

अतिक्रमणकारी

एक व्यक्ति/परिवार जो अपनी समीपवर्ती भूमि या अन्य अचल सम्पति के साथ सार्वजनिक भूमि में अतिक्रमण करता है (अन्तिम तारीख से पहले) और अपना आश्रय/आजीविका का अतिरिक्त स्त्रोत प्राप्त करता है।

स्कवैटर्स

ऐसा व्यक्ति/परिवार जो बिना अनुमति के सार्वजनिक भूमि पर स्थापित हो गया है या अंतिम तारीख से पहले बिना किसी प्राधिकार के सार्वजनिक भवन का इस्तेमाल कर रहा है और अपने आश्रय/आजीविका के लिए निर्भर है और उसका कोई आश्रय या आजीविका का स्त्रोत नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव

महाराष्ट्र में डीएफसी के लिये भूमि अर्जित करने हेतु मुआवजे का दर निर्धारित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने डीएफसीसीआईएल के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु दर निर्धारण करने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया है। इसके अनुसार समिति में कलेक्टर (चेयरमैन), एस एल ए आफिसर/सक्षम प्राधिकारी (सदस्य सचिव) और 8 अन्य सदस्यों की समिति बनेगी।

भूमि का दर निर्धारित करने के लिए, समिति, इनटाइटिलमेन्ट मैट्रिक्स का नोट–क, आर आर ए 2008 का पैरा 20 जी और अन्य जैसे कि पी ए पी के दावे, संयुक्त माप सर्वेक्षण के परिणाम, भूमि के बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की खोज, आसपास की जगहों के स्थानीय फैक्टर जो कि विषय भूमि की कीमत से सम्बन्ध रखते हो, को विचार में ले सकते हैं।

समिति रेडी रेकनर व उसी वर्ष के सेल्स डीड की दरों की तुलना करेगी एवं भूस्वामी को उच्चतम दर का प्रस्ताव करेगी।

अगर भू–स्वामी प्रस्तावित दर से सहमत नहीं होता है तो समिति गॉव वालों को स्वीकार्य दर का पता लगाएगी एवं उसी को डीएफसीसीआईएल के पास मंजूरी के लिए सिफारिश करेगी और फिर समिति तदनुसार दर निर्धारित करेगी।

समिति निरपवाद रूप से महीने में एक बार विचारणीय गॉवों के दर निर्धारण हेतु मिलेगी। समिति, महाराष्ट्र राज्य के अन्तर्गत डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की योजना के लिए उन सभी गॉवों के लिए दर को अन्तिम रूप देगी एवं सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति एवं संवितरण के लिए सलाह देगी।

संस्थागत व्यवस्थाएं

डीएफसीसीआईएल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते परियोजना के समस्त तकनीकी पहलुओं और उनके कार्यान्वयन तथा उधार ली गई राशि की निगरानी और समस्त कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल संगठन का मुखिया होने के नाते आर ए पी के सफलतापूर्वक

क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। डीएफसीसीआईएल ने पहले ही सूरत, मुम्बई और नोएडा में परियोजना प्रबंध इकाई का कार्य करने के लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय (सीपीएम आफिस) स्थापित कर दिए हैं और महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है। प्रधान कार्यालय में एक पर्यावरण और सामाजिक इकाई(सेमू) महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में स्थापित की गई जिसका काम भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनः स्थापना प्रक्रिया देखना है। प्रधान कार्यालय और परियोजना कार्यालय का संगठनात्मक ढाँचा चित्र 1 और चित्र 2 में दर्शाया गया है।

चित्र:–1 प्रधान कार्यालय का संगठनात्मक ढाँचा

चित्र:–2 परियोजना कार्यालय का संगठनात्मक ढाँचा

कार्यान्वयन सूची

No.	कार्रवाई	2010 3Q	2010 4Q	2011 1Q	2011 2Q	2011 3Q	2011 4Q	2012 1Q	2012 2Q	2012 3Q	2012 4Q	2013 1Q	2013 2Q	2013 3Q	2013 4Q	2014 1Q	2014 2Q	2014 3Q	2014 4Q
1	Preparation of Land Plan	■	■	■	■														
2	Notification under Section 20A of RAA-2008	■	■	■	■	■	■												
3	Hearing of Objections	■	■	■	■	■	■												
4	Identification of Plot Owner	■	■	■	■	■	■												
5	Notification under Section 20E of RAA-2008	■	■	■	■	■	■	■											
6	Joint Verifications (Joing Measurement Survey)	■	■	■	■	■	■	■											
7	Baseline Survey and Census	■	■	■	■	■	■	■											
8	Preparation of Draft RRP				■	■	■	■											
9	Disclosure of Draft RRP				■		■	■											
10	PCMs for Draft RRP				■		■												
11	Finalization of Entitlement Matrix				■		■												
12	Preparation of Final RRP				■		■	■											
13	Disclosure of Final RRP						■	■											
14	Preparation of Compensation for Land and R&R	■	■	■	■	■	■	■	■										
15	Award of Compensation as per Section 20F of RAA-2008	■	■	■	■	■	■	■	■										
16	Deposit of Money with CA	■	■	■	■	■	■	■	■										
17	Disbursement of Payment to PAPs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
18	Taking possession of Land									■	■	■							
19	Execution of Work										■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	Monitoring of Resettlement Impact (Internal)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21	Monitoring of Resettlement Impact (External, bi-annual)								■		■		■		■				
22	Grievance Redressal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

चित्र: 1 पुनर्वास कार्यक्रम (अस्थायी)

<u>शिकायत निपटान तंत्र</u>– एन आर आर पी 2007, सेक्शन 8.1 के अनुसार मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर पी ए पी/ पी ए एफस और अन्य किसी भी स्थानीय निवासी जो कि डीएफसी की परियोजना को लागू होने में शिकायत करता है, के निवारण हेतु पुनःस्थापना एवं पुनर्वास समितियाँ होंगी।

क्षेत्रीय स्तर पर शिकायत निपटानः

(1) मुख्य परियोजना प्रबन्धक की अगुवाई में पुनःस्थापना एवं पुनर्वास समिति होगी जिसके अन्तर्गत निम्न लोग होंगे–

(क) सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर या उनके नामित (चेयर)
(ख) सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी (आमंत्रित)
(ग) सम्बन्धित सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर– सामाजिक (सचित लोक सेवा प्रदान करने के लिए)
(घ) जिला परिषद अध्यक्ष या उनका/उनकी नामित
(ङ) सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि/स्थानीय प्रतिष्ठित एन जी ओ

(2) प्रोजेक्ट स्तर पर शिकायत निपटान

महाप्रबन्धक (सेमू) की अगुवाई में–
(क) डाइरेक्टर (इनफ्रास्ट्रकचर)
(ख) उप महाप्रबन्धक–शिकायत
(ग) सामाजिक विशेषज्ञ और
(घ) रेल मंत्रालय का प्रतिनिधि

(3) आर्बीट्रेटर की भूमिका– इस मामले में, सम्बन्धित राजस्व डिवीजन के कमिश्नर जो कि, 15 जुलाई,2010 के राजपत्र द्वारा नियुक्त किये जा चुके है, आर्बीट्रेटर होंगे और आर आर ए 2008 के अनुसार पी ए एफस को देय मुआवजे से सम्बन्धित शिकायत को सुनेंगे व निपटान करेंगे।

(4) रेल मंत्रालय एक लोकपाल की नियुक्त करेगा जो कि ऐसी शिकायतों का निपटान करेगा, जो डीएफसीसीआईएल द्वारा गठित पुनः स्थापना व पुनर्वास समिति द्वारा न निपटाया जा सकता हो।

डीएफसी में कार्पोरेट स्तर पर शिकायत निपटान प्रणाली

(1) क्षेत्रीय स्तर पर शिकायत निपटान प्रणाली

कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य सम्पत्तियों से संबंधित शिकायत प्रारम्भिक तौर पर मु0 परियोजना प्रबन्धक कार्यालय द्वारा निपटान होगा। अगर कागजातों की जॉच वास्तविक लगते है तो मु0 परि0 प्रबन्धक ही उसे हल करेंगे। अगर उनके स्तर पर हल नहीं हो सकता है, तो उसे मुख्यालय को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) कार्पोरेट स्तर शिकायत निपटान प्रणाली

1. एक केंद्रीकृत शिकायत निपटान प्रणाली जिसमें एक परियोजना योजनामचा के साथ–साथ प्राप्त शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति को दर्शाते हहुए एक प्रणाली की स्थापना डीएफसीसीएल द्वारा की जाएगी।

2. शिकायत निपटान प्रणाली एम आ आर ओर मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित की जायेगी।

3. शिकायत रजिस्ट्रर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और कार्पोरेट स्तर पर प्रत्येक समूह महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के पास रख दिया गया है। संबंधित कार्यालय द्वारा प्राप्त सभी शिकायतें इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। सतर्कता कोण वाली शिकायतों को संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास भेजा जाएगा।

4. प्राप्त शिकायतों के निपटान की निगरानी के लिए महाप्रबंधक/प्रौद्यो. को नामित किया गया है जो मासिक आधार पवर निदेशक मंडल को स्थिति प्रस्तुत करेंगे।

5.प्रत्येक मामले की स्वचालित उत्पत्ति, मानक प्रपत्र रिपोर्ट सभी प्राप्त शिकायतों के रिकार्ड और निपटान की जिम्मेदारी डीएफसीसीआईएल की होगी।

6. डीएफसी सभी शिकायतों, चाहे वे किसी भी स्त्रोत से प्राप्त हुई हों, का उत्तर सामान्यतः प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर देगी।

7. टिप्पणियों, सुझावों और शिकायतों के निपटान से संबन्धित एक घटक वैबसाइट (http:www.dfccil.org) पर शामिल किया जाएगा। इसे मासिक आधार पर अद्यतन किया जायेगा। शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतों की आनलाइन ट्रैकिंग में भी यह साइट सक्षम होगी।

8. जांचों की स्थिति की ट्रैकिंग और लिए गए उपायों को प्रबंधन के पास जाने वाली मासिक रिपोर्टों में दर्ज किया जाएगा।

9. शिकायत तंत्र के कार्यकुशल संचालन के लिए संबंधित सूचना को शिकायत के विभिन्न माध्यमों जैसे वैबसाइट, कार्यस्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना पट्टों पर विस्तार से प्रकाशित किया जाएगा।

लागत अनुमान

अनुमानित बजट आर आर पी द्वितीय चरण के मुख्य रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

आर आर पी रिपोर्ट का वितरण

विस्तृत सूचनाओं के साथ, आर आर पी रिपोर्ट निम्नलिखित जगहों पर उपलब्ध होगी।

– आर आर पी रिपोर्ट का सारांश स्थानीय भाषा (हिन्दी या गुजराती या मराठी) में प्रत्येक प्रभावित गॉवों में

– आर आरपी रिपोर्ट का सम्पूर्ण भाग– अंग्रेजी भाषा में सम्बन्धित मु0 परि0 प्रबन्धक कार्यालय, डीएफसीसीआईएल मुख्यालय, प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं जिला कलेक्ट्रेट

कार्यालयों में सम्बन्धित संगठनों के सम्पर्क सूत्र

मुख्य परियोजना प्रबन्धक मुम्बईः– सातवीं मंजिल, न्यू ऐडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सेन्ट्रल रेलवे–डीएन रोड, मुम्बई 400001, महाराष्ट्र

मुख्य परियोजना प्रबन्धक सूरतः– चौथी मंजिल, अरूणस–1 इजकोन मॉल के पास, दूमास रोड, पीपलोड, सूरत– 395007, गुजरात

मुख्य परियोजना प्रबन्धक वडोदराः– 13–14, 17–18, पनोरामा कोम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, आर.सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा–395007, गुजरात

मुख्य परियोजना प्रबन्धक नोएडाः– स्टार हाउस, फर्स्ट फ्लोर, ए–102, सेक्टर–4, नोएडा, उत्तर प्रदेश

सक्षम प्राधिकारीः–

1. जिला रायगढ़: काम्पीटेन्ट आथोरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इक्यूजीसन) रायगढ़, मेट्रो सेन्टर न.0–1, उडान,रायगढ़, सीआइडीसीओ नोदाल ऑफिस, इंजीनियरिंग सेक्शन, द्रोणानगरी, सेक्टर–14, बोकडवीरा, तौलका उडान,रायगढ़

2. जिला थानेः– काम्पीटेन्ट आथोरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इक्यूजीसन आफिसर), वेस्टर्न फ्रेट कोरीडोर, सूर्या प्रकल्प, ईरानी रोड, ओपीपी, आईडीबीआई बैंक,

3. जिला वलसादः– काम्पीटेन्ट आथोरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इक्यूजीसन आफिसर), सेकण्ड फ्लोर, जिला सेवा सदन–2, कलेक्टर ऑफिस, वलसाद

4. जिला नवसारीः– डिप्टी कलेक्टर और काम्पीटेन्ट आथोरिटी, फर्स्ट फ्लोर, "सी" ब्लॉक, मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग, जनाथना, नवसारी

5. जिला सूरतः– काम्पीटेन्ट आथोरिटी और स्पेशल लेण्ड इक्यूजीसन ऑफिसर, ब्रान्च नं0.4, पाचवीं मंजिल "ए" ब्लॉक, बहुमाली भवन, सूरत

6. जिला बहुरवः– :– काम्पीटेन्ट आथोरिटी और स्पेशल लेण्ड इक्यूजीसन ऑफिसर, लेण्ड इक्यूजीसन ब्रान्च, कलेक्टर ऑफिस, बहुरव

7. जिला वडोदराः– स्पेशल लेण्ड इक्यूजीसन ऑफिसर यूनिट नं0.1, रूम नं0–815, छठी मंजिल, कुबेर भवन, कोठी कम्पाउन्ड, वडोदरा

8. जिला रेवाड़ीः– डिस्ट्रीक्ट रेवन्यू ऑफिसर(डी आर ओ), डी सी ऑफिस, मिनी सेक्रेटरियट, रेवाड़ी

9.जिला अलवरः– सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट (सीडीएम)/एसडीओ, एसडीएम/तिजारा, तहसील तिजारा, अलवर

10. जिला मेवातः– डिसट्रिक्ट रेवन्यू ऑफिसर(डीआरओ),डीसी ऑफिस, डिसट्रिक्ट सेकेटरियट, नूह, मेवात

11. जिला गुडगाँवः– डिसट्रिक्ट रेवन्यू ऑफिसर(डीआरओ), मिनी सेकेटरियट,गुडगाँव

12.जिला पलवलः– सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम),एसडीएम ऑफिस, पलवल

13. जिला फरीदाबादः– डिस्ट्रीक्ट रेवन्यू ऑफिसर (डीआरओ),मिनी सेकेटरियट, सेक्टर–12,फरीदाबाद

14. जिला गौतमबुद्ध नगरः– सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम (सदर,) डीएम ऑफिस, गौतमबुद्ध नगर

सेमू, डीएफसीसीआईएल हेड ऑफिसः– प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, न्यू दिल्ली– 110001

[Gujarati]

MOR/DFCCIL

રેલ્વે મંત્રાલય / ડેડીકેટેટ ફ્રેઈટ કોરીડોર કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા

સમર્પિત માલવાહક પરિયોજના Phase 2ની પુનર્વાસ તેમજ પુનર્સ્થાપન નીતિ અને વિધાન (RRP)

વડોદરાથી મુંબઈ (JNPT)
અને
રેવાડીથી દાદરા

સુચિત

નવેમ્બર - ૨૦૧૧

પરિયોજના પર એક નજર

રેલ્વે મંત્રાલય, દિલ્હી અને મુંબઈ મહાનગર સુધી તેમજ આસ-પાસના સ્થાળો પરથી ઓછા સમયમાં માલ-સામાનનો અવરોધ રહિત (ઝડપી) સરળ અને ઓછા ખર્ચે પરીવહન થઈ શકે તે હેતુથી કોમ્પ્યુટર સંચાલિત બહુઆયમી ઉચ્ચ એક્સલ લોડ વાહન ક્ષમતા ધરાવતી સમર્પિત માલવાહક પરિયોજના (DFC) નું આયોજન તેમજ અમલીકરણ કરી રહ્યો છે.આ પરીયોજના ને વર્ષ ૨૦૧૩ -૨૦૧૪ માં ૩૭.૭ મિલિયન ટન માલ પરિવહન માટે ડિઝાઈન તૈયાર કરવામાં આવેલ છે, જે ૨૦૩૩-૨૦૩૪ સુધીમાં ૧૪૦.૪ મિલિયન ટન થઈ જશે. પરિયોજના અત્યારે આયોજન ના તબક્કે છે, તેની શરૂઆત ૨૦૦૬ માં કરવામાં આવી હતી. અને વર્ષ ૨૦૧૨માં પૂર્ણ થશે. પરિયોજનાનુ નિર્માણ કાર્ય ૪ થી ૫ વર્ષ માં (વર્ષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૬ વચ્ચે) પૂર્ણ થશે. વર્ષ ૨૦૧૬ ના ડિસેમ્બરથી યોજના નુ વ્યાપારિક ધોરણે કાર્યાન્વયન પ્રારંભ થશે.

સામાન્ય વિશેષતાઓ :-

* કોરિડોરની લંબાઈ :- ૫૬૫ કિ.મી.
* અનુભાગની લંબાઈ :– વડોદરાથી મુંબઈ: અંદાજે ૪૨૦ કિ.મી. રેવાડીથી દાદરી: અંદાજે ૧૪૫ કિ.મી.
* જન્કશન સ્ટેશન- :- ૯: ક્રોસીંગ સ્ટેશન:-૧૧, મોટા મહત્વના પૂલો :-૧૬૫
* પ્રસારિત રેલ માર્ગ :- ગુજરાત, રાજસ્થાન, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર-પ્રદેશ અને દિલ્હી.
* અસરગ્રસ્ત જિલ્લા :- ૧૪
* અસરગ્રસ્ત ગામો :- ૩૭૪ (હંગામી)
* પહોળાઈ :- સમાન્તર અનુભાગમાં લગભગ ૩૫ મીટર અને બાઈપાસ વિભાગ માં ૬૦ મીટર
* અધિકતમ ગતિ મર્યાદા :- ૧૦૦ કિમીટર/પ્રતિ કલાક

પરિયોજનાથી થનાર લાભ :-

ડી.એફ.સી. પરિયોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતના વર્તમાન વિકાસ દરને ને ઝડપી બનાવવાનો અને પર્યાવરણમાં સુધારો લાવવાનો છે.
* ભારતમાં માલ-સામાન પરિવહન પ્રમાણલીમાં સુધારો કરી દેશની આર્થિક ઉન્નતિમાં વધારો કરવો.
* ડી.એફ.સી. સમાન્તર ઔદ્યોગિક વિકાસ ના વધારાથી આર્થિક ઉન્નતિ અને રોજગારની નવી તકો ઊભી થશે.
*કૃષિ ઉત્પાદનોના પરિવહન પ્રાણાલીમાં ગતિ સમ્બધિત સુધારો કરી ક્ષેત્રના ખેડૂતો તેમ જ વન્ય ઉત્પાદનો તેમજ મત્સ્ય પાલનનાં બજારમાં વિસ્તાર તેમજ સુધારો કરી આર્થિક ઉન્નત્તિમાં વધારો કરવો.
* ટ્રકો દ્વારા પરિવહન કરતા નાના વાહનોના પ્રમાણમાં ઓછી ઊર્જા.
* ડી.એફ.સી. માર્ગથી બાજુ સ્થિત સ્થાનિક રહેવાસીઓ ને કોઈપણ પ્રકારે વાયુ પ્રદૂષણ થશે નહી. (આ માર્ગ ની સાથે-સાથે ટ્રકો દ્વારા ઉત્પન્ન થતા પ્રદૂષણથી બચાવ).

ડી.એફ.સી. પરિયોજના માટે જમીન સંપાદનનું Phase 2 સ્વરૂપ :-

ડી.એફ.સી. માર્ગ વડોદરા, સુરત, વસઈ, જ.ને . પો. ટ્ર. અને રેવાડી થી દાદરી પસાર થાય છે. પરિયોજનાના અમલીકરણ, વ્યવસ્થા અને સંચાલન માટે પછી સ્વરુપનું જમીન સંપાદન તેમજ પુનર્વાસ જેવા મહત્વનાં પરિબળોની આવશ્યક્તા પડશે. સ્થાનીય મકાનોની તોડ-ફોડ, શહેરી સ્થાનીય સમુદાય, જીવઅભ્યારણ, શહેરી યોજનાક્ષેત્ર, માર્બલ ઉદ્યોગ, આબાદી ક્ષેત્રો, ખાણો વગેરેની તોડ-ફોડ ને બચાવવા તેમજ ન્યૂનત્તમ જમીન સંપાદન થાય તે હેતુ બાઈપાસ આપવામા આવ્યો છે. હરિયાણા તેમજ રાજસ્થાનમાં આ માર્ગ વર્તમાન રેલ્વેમાર્ગ ની સમાન્તર તેમજ પૂર્વ દિશામાં છે, જ્યારે સુરત,દહાણુ,વસઈ કુંડ બહાર અને રેવાડી-દાદરીમાં આ માર્ગ વર્તમાન રેલ્વે લાઈનની પૂર્વ દિશામાં બાઈપાસ માર્ગ છે. તેમ છતા પણ બન્ને અનુભાગો સમાંતર અને બાઈ પાસ વિભાગમાં જમીન સંપાદન કરવાની આવશ્યકતા પડશે.

અમલીકરણ સંસ્થા (EA):

ડેડીકેટેટ ફ્રેઈટ કોરીડોર કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (DFCCIL)

પરિયોજનાની જમીન સંપાદન અને પુનર્વાસ તેમજ પુનર્સ્થાપનની આધારભૂત નીતિ અને વિધાનઃ-

*** રેલ્વે એમેંડમેંટ એક્ટ, ૨૦૦૮(આર. આર. એ. ૨૦૦૮)**
આ અધિનિયમ થી ડી.એફ.સી. પરિયોજના(વિશેષ રેલ પરિયોજના જાહેર) માટે જમીન સંપાદન કરવામાં આવી રહ્યુ છે. આ અધિનિયમમાં જમીન સંપાદન અધિનિયમ ૧૮૯૪ લાગુ પડતો નથી.

*** રાષ્ટ્રીય પુનર્વાસ અને પુનર્સ્થાપન નિતિ,૨૦૦૭**
ડી.એફસી. પરિયોજના માટે જમીનનું ઓછી પહોળાઈ અને લાંબી પટ્ટીઓમાં સંપાદન કરવામાં આવનાર છે. ડી.એફ.સી. પરિયોજનાની રેલ પરિયોજના માટે એન.આર.આર.પી. ૨૦૦૭ નાં ખંડ ૭.૧૯ માં ઉલ્લેખિત અનુરેખીય જમીન સંપાદન નિયમ મૂલતઃ લાગુ પડે છે.

*** સક્ષમ અધિકારી**
સક્ષમ પ્રાધિકારી એવી વ્યક્તિ નિયુક્ત છે, કે જેને કેન્દ્રિય સરકાર દ્વારા એ ક્ષેત્રનાં સંદર્ભમાં સક્ષમ પ્રાધિકારીનાં કાર્યોનું પાલન કરવા માટે પ્રાધિકૃત કરવામાં આવ્યા છે. જેના નામ જાહેર નામામાં વિનિર્દિષ્ટ કરવામાં આવશે.

રેલ્વે એમેંડમેંટ એક્ટ, ૨૦૦૮ અનુસાર હિતબધ્ધ વ્યક્તિ
૧. આ નિગમના અધિન જમીન આપવાના સંબધમાં આપતામાં આવેલ પ્રતિકારમાં કોઈ હિત ના દાવો કરવાવાળી વ્યક્તિઓ.
૨. દરેક જન જાતિઓ અને પરંપરાગત વન નિવાસી, જેઓને અનુસુચિત જન જાતિ અને અન્ય પરંપરાગત વન નિવાસી (વન અધિકરોની માન્યતા) અધિનિયમ, ૨૦૦૬ અધિન માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈ પરંપરાગત અધિકાર ગુમાવી ચુક્યા હોય.
૩. રાહત લેવામાટે ઈચ્છુક એ વ્યક્તિ કે જે જમીન સંપાદિત થવાથી પ્રભાવિત થાય છે.
૪. રાજ્યના કાયદાઓ અધિન ગણોત અધિકાર રાખવાવાળી વ્યક્તિ.

નિદેશિત તારીખઃ-
આર.આ.એ. ૨૦૦૮/ એન.આ.આર.પી. ૨૦૦૭ ના આધારિત યોગ્ય તારીખ.
હિતધરાવનાર કે જમીન અધિકાર ન ધરાવનાર વ્યક્તિઓ માટે પાત્રતાની એ તારીખ છે જ્યારે આર. એ.એ. ૨૦૦૮ નાં કલમ ૨૦Aનાં અર્ન્તગત જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થાય છે.

પુનર્વાસ અને પુનઃસ્થાપન નિતિ (RRP)

પુનર્વાસ અને પુનર્સ્થાપન નીતિ (**RRP**) એવા સિધ્ધાંતો પર આધરિત છે કે પરિયોજના પ્રભાવિત વ્યક્તિની (**PAPs**) સ્થિતિ, પરિયોજના પહેલાની સ્થિતિ કરતા સારી રહેશે.

નિતિ અનુસાર પુનર્વાસ અને પુનઃસ્થાપન યોજનાનાં ઉદ્દેશ્ય : -
* પરિયોજના પ્રભાવિત પરિવરોની સ્થિતિ પરિયોજનાને કારણે પહેલાની સ્થિતિ કરતા સારી રહેશે.
* ઓછુમાં ઓછુ વિસ્થાપન, વિસ્થાપન ન થાય તેમ જ ઓછામાંઓછુ વિસ્થાપન થાય તેવા વિકલ્પોની પસંદગી.
* પ્રભાવિત વ્યક્તિઓની સક્રિય ભાગીદારીની સાથે પુરતુ પુનર્વાશ પેકેજ સુનિશ્ચિત કરી તેમજ પુનર્વાસ પ્રક્રિયાનું કાર્ય ઝડપથી પૂર્ણ કરવું.
* સમાજનાં નબળા વર્ગો/**અસુરક્ષિત** વર્ગો (**વરનેરેબલ ગ્રુપ**) વિશેષ રુપથી અનુસુચિત જાતિઓં, અનુસુચિત જન જાતિઓં તેમજ આશ્રિતોં અને મહિલાઓ, વૃદ્ધો તેમજ અપંગો ના પુનર્વાસનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું .
* પ્રભાવિત પરિવારો ને સુવ્યવિસ્થ જીવન ધોરણ ઉપલબ્ધ કરાવી, સતત આવક મળી રહે તેનું આયોજન કરવું.
* જમીન સંપાદન કરવા વાળા સંપાદન સંસ્થા તેમજ પ્રભાવિત પરિવારો વચ્ચે આપસી સહયોગ દ્વારા મૈત્રી પૂર્ણ સંબધ બની રહે.
***જમીનનો કબજો લેતા અને કોઇ પણ નિર્માણ કાર્ય શરૂ કરતા પહેલા વળતર તેમજ પુનઃ સ્થાપન રાશિની ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવી.**

__વળતરની નીતિ :-__
* જમીન સંપાદન કરવાની જવાબદારી રેલ મંત્રાલય દ્વારા નિયુક્ત સક્ષમ પ્રાધિકારીની રહેશે.
* જમીન આપનાર વ્યક્તિઓને વળતરની રકમ, આર.એ.એ. ૨૦૦૮ અનુસાર આપવામાં આવશે. બજાર કિંમત આર. એ. એ.૨૦૦૮ના અનુસાર નિર્ધારિત કરવામાં આવશે. જમીન સંપાદન કરવાની અનિવાર્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને દરેક નિયત કિસ્સામાં જમીનની બજાર કિંમત કરતા તેની કિંમતના ૬૦(%) ટકા વધુ આપવામાં આવશે. ((સેક્સન૨૦F, (૯), આરએ.એ.,૨૦૦૮), આર.એ.એ.૨૦૦૮માં નિર્દેશીત જોગવાઇ પ્રમાણે.)

નહિતર સક્ષમ પ્રાધિકારી, એવા કિસ્સામાં જ્યાં રાજ્ય સરકારે, કોઇ અધિનિયમ અથવા ગઝેટ નોટીફિકેસન અથવા રાજ્ય સરકારના કોઇ અન્ય સત્તાધિકારી (જેમને આ બાબતે સત્તાધિકાર મળવો હોય) એ યોગ્ય પ્રક્રિયા દ્વારા ભુમિસંપાદન માટેની કિંમત/દર નક્કી કર્યુ હોય, તો તે પણ, ભુમી સંપાદનનું વળતર નક્કી કરવા, આર. આર. એ. ૨૦૦૮ ની નિર્દેશિત જોગાવઇ નાં બદલે સ્વીકારી શકે છે.
* જમીનથી હિતબદ્ધ કોઈ વ્યક્તિ, જમીન સંપાદનના જાહેરનામાંની રાજપત્રમાં પ્રસિદ્ધીની તારિખ થી ત્રીસ દિવસની અંદર જમીન સંપાદન બાબતે વાંધો જાહેર કરી શકે છે. (સેક્સન ૨૦ **D**(૧), આર.એ.એ.,૨૦૦૮).
* ભવન અને અન્ય અચલ સંપત્તિ, વૃક્ષો, ઝાડ તેમજ તે જમીન પર ઊભા પાક જે સંપાદિત કરવામાં આવશે તેની બજાર કિંમત સુસંગત ક્ષેત્રમાં કોઈ વિશેષજ્ઞ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. (સેક્સન ૨૦ **G**, (૪,૫,૬),આર.એ.એ.,૨૦૦૮)
* જમીન સંપાદન ત્યારે પૂર્ણ સમજવામાં આવશે કે જ્યારે જમીનનું સંપાદન અધિકારપત્ર સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવેલ અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવશે તેમજ વર્તમાન નિયમો મુજબ વળતર નક્કી કરવામાં આવશે.
* વળતરની રકમની ચુકવણી જમીન સંપાદન કર્યાના જાહેર નામાની પ્રસિદ્ધી પછી એક વર્ષમાં કરવામાં આવશે. અનિવાર્ય પરિસ્થિતિમાં આ મુદત છ મહિના સુધી વધારવામાં આવશે(**જો વધારેલ મુદ્દત માં એવર્ડ બનાવવામાં આવે તો**). **હકધરાવનાર વ્યક્તિને,એવાર્ડમાં મોડુ થવાથી** વધારાની મુદતમાટે દરેક મહિને નક્કિ કરવામાં આવેલ વધારાના વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવશે. (સેક્સન ૨૦ **F**(૧,૨,) આર.એ.એ.,૨૦૦૮)
* જો હિતબદ્ધ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા વળતરની રકમ પર અધિકાર મેળવવા માટે વળતર મેળવવાની સુચનાનાં એક વર્ષમાં દાવો નહિ કરવા આવે તો આ રકમ કાર્યાન્વયન સંસ્થાની પાસે અલગ ખતામાં પરિયોજના પુરી થાય ત્યાં સુધી રાખવામાં આવશે. **હિતબદ્ધ પક્ષ, સીધા અથવા તેમના કાનુની ઉત્તરાધિકારી દ્વારા, દસ્તાવેજોના સંતોષકારક તપાસ પછી., પોતાના વળતર ની રકમનો દાવોકરી શકે છે.**
* આ અધિનયમ દ્વારા જમીન સંપાદન પ્રક્રિયામાં જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ લાગુ પડતો નથી.
* અનુરેખીય જમીનનાં સમ્પાદન બાબતે જેમકે રેલેવે લાઈનમાં ફક્ત ઓછી પહોળાઈ વાળી પટ્ટીઓમાં **પરિયોજના માટે** જમીન સંપાદન કરવામાં આવે છે, પ્રમાવિત પરિવારો ના પ્રત્યેક ખાતેદારો ને એટલી રકમ આપવામાં આવશે કે જે સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવશે, આ નિર્ધારિત **રકમ ઓછામાં ઓછી** રૂપિયા ૨૦,૦૦૦થી ઓછી હશે નહિ. **વળતર ઉપરાંત અન્ય લાભો, જે જમીન, ઘર અથવા અન્ય સંપતિનું સંપાદન માટે લાગૂ અધિનિયમ/નિતિ ને આધીન કેમ છે. તે મળવાપાત્ર છે. (RRP2007).** પરંતુ જો આવી જમીનનાં સંપાદનથી જમીનવાળા કિસાનો જમીન વગરના બની જાય છે અથવા નાના તેમજ સીમાન્ત ખેડૂતોની શ્રેણીમાં આવી જાય છે, તો તે પુનર્સ્થાપન સહાયતા ના રૂપમાં ૭૫૦ દિવસનુ કૃષિ વેતન મેળવવા પાત્ર છે.

__પરિયોજના માટે પુનર્વાસ અને પુનર્સ્થાપન માટેના મુખ્ય સિદ્ધાંતોઃ-__

* પરિયોજના પ્રભાવિત વ્યક્તિઓ/પરિવારોં (**PAPs/PAFs**) ને હિતધરાવનાર વ્યક્તિઓ, હિત ન ધરાવનાર વ્યક્તિઓ ભાડુઆત, જમીનનો પ્લોટ વાપરનાર, બુથ(કાચા માલ સામાનથી બનાવેલ દુકાનો), ફેરિયા, વેપારીઓ વગેરેને વર્ગિકૃત કરવામાં આવશે.
*વિભિન્ન વર્ગોના (**PAPs/PAFs**)પરિયોજના પ્રભાવિત પરિવારોને "મૌલિક પાત્રતા" અનુસાર ક્ષતિપુર્તિ તેમજ સહાયતા આપવામાં આવશે.
* (**PAPs/PAFs**) પરિયોજના પ્રભાવિત પરિવારો જીવન-ધોરણમાં સુધારાઓ લાવવા માટે સહાયતા આપવામાં આવશે.
* મૌલિક પાત્રતા અનુસાર પરિયોજના પ્રભાવિત પરિવારોને પુનર્વાસ અને પુનર્સ્થાપન માટે અતિરિક્ત સહાયતા આપવામાં આવશે.
* પરિયોજના પ્રભાવિત પરિવારોની નુકશાન પામેલ સંપતિની ક્ષતિપૂર્તિ માટે પરિયોજના પ્રભાવિત વ્યક્તિઓ ને પુનઃ સ્થાપન માટે વળતર આપવામાં આવશે.
* નિર્દેશતિ તારીખ પછી જો કોઈ પરિયોજના ક્ષેત્રમાં આવેતો તે આ સહાયતા માટે હક્ક ને પાત્ર રહેશે નહિ.
* આ પરિયોજના ના પુનઃ સ્થાપન માટે અલગથી બજેટ હશે.
*લોકોની ભાગીદારી માટે ગામો/જિલ્લા સ્તર જમિન માલિકો સાથે લોક સંવાદ બેઠકો યોજવામાં આવશે.
* ફરિયાદો ના જલ્દી સમાધાન માટે ઉપયુક્ત ફરિયાદ નિવારણ કેન્દ્રોની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
* જમિન માલિકો તેમજ પરિયોજના પ્રભાવિત પરિવારોની સાથે થયેલ વિચાર વિમર્ષોને દસ્તાવેજીત કરવામાં આવશે. આના દ્વારા એ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે કે આ અર્થપૂર્ણ બાબતો પુનર્વાસ અને પુનર્સ્થાપન યોજના દરમિયાન જળવાય રહે.

ક્ષતિપૂર્તિ, સહાયતા અને પુનર્વાસ માટેની યોગ્યતાઃ-
-પાત્રતા માટેની **નિદેશિત/અંતિમ** તારીખ એ તારીખ છે **કે જ્યારે** પ્રભાવિત ક્ષેત્રમાં, કાયદાકીય માલિકો અને હિત નધરાવનારા માટે, આર.એ.એ. ૨૦૦૮ ની કલમ ૨૦A **ને આધીન** જાહેરનામા અનુસાર અધિસુચના જાહેર કરવામાં આવે છે.
-પરિયોજના પ્રભાવિતો ની **વિવિધ શ્રેણીઓની પાત્રતા /યોગ્યતા નીચે દર્શાવેલ** અનુવર્તિત સેકશન માં બતાવવા માં આવેલ "મૌલિક પાત્રતા"(**entitlement Matrix**) અનુસાર કરવામાં આવશે.
- **પાત્રતા /યોગ્યતા** માટેનું એકમ પરિવાર હશે.
-**પ્રભાવિત** પરિવાર વળતરની સાથે સાથે ક્ષતિ પૂર્તિ માટે પણ સહાય પાત્ર છે.
-એવા પરિવારો કે જેઓના દ્વારા ઉપયોગમાં લેનાર ભૂમિ પર હક્ક નથી ધરાવતા તેવા પરિવારો વળતર માટે હક્કદાર નથી. પરંતુ જો **અતિક્રમણ**/દબાણ કરનારાઓ(**મૌલિક પાત્રતા ની નોટ F ની વ્યાખ્યા અનુસાર**) ને ત્રણ માસ આગોતરી નોટીસ આપવામાં ન આવી હોય તો તેઓને મકાનો **અથવા** પાક

અથવા સંપતિઓની સ્થાપનાની કિમંત અનુસાર વળતર મળશે. પુનર્વાસ અને પુનર્સ્થાપન નિતી અનુસાર મૌલિક હકકપાત્રતા મુજબ પ્રભાવિત વ્યક્તિઓ વિવરણ એફ મુજબ સહાયતાને પાત્ર છે.

-જો કોઈ પરિવાર યોજના ક્ષેત્રમા પ્રભાવિત પરિવારોની ગણના મુજબ જો કોઈ પરિવારની ગણના કરવામાં આવી નહોય તો, **અનેતેની પાસે પ્રભાવિત ક્ષેત્રમાં તેની ઉપસ્થિતિ, અંતિમ તારિખ પહેલા હોવાના પુરાવાઓ હોય તો ફરિયાદ નિવારણ સમિતિ દ્વારા વિધિવત સત્યાપન પછી, તેને PAP/PAF નો સુચિતાં સામેલ કરાશે.** તે પુરવાઓ સહિત અંતિમ તારીખ પહેલા ફરિયાદ નિવારણ સમિતિ દ્વારા ખરાઈ કરીને તેને પ્રભાવિત પરિવારોની ગણનામાં સામેલ કરવામાં આવશે.

-પ્રભાવિત વ્યક્તિઓ તોડવામાં આવેલ માળખા ના કાટમાળ ને કોઈ બાધા વગર પરિયોજના ને વિલંબિત કર્યા વગર લઈ જઈ શકે છે.

-જો કોઈ વ્યક્તિ અથવા પરિવારને અંતિમ તારીખ પહેલા નોટિસ આપવામાં આવેલ છે અને જો તે કોર્ટ **કેસ ચાલુ હોય** તો આવી સ્થિતિમાં ન્યાયાલય દ્વારા કાયદાકીય સ્થિતી નિર્ધારિત કર્યા અનુસાર કરવામાં આવશે તેમજ **RRP**ના પ્રાવધાનો અનુસાર **PAP/PAF ની યોગ્યતા માટે કોર્ટ દ્વારા નિર્ધારિત કાયદા કોય સ્થિત ગણમાન્ય કરાશે.** પરિયોજના પ્રભાવિત વ્યક્તિ અથવા પરિવાર ને વળતર તેમજ સહાયતા ને પાત્ર ગણાશે.

નં	પ્રકાર	પ્રભાવિત વ્યક્તિઓની વ્યાખ્યા	યોગ્યતા	વિવરણ /માહિતિ
ક). પ્રાઈવેટ ખેતી લાયક ભૂમિ, રહેણાંકની ભૂમી અને ધંધા માટેની ભૂમિને થતી નુકશાની				
૧	પરિયોજનાના રસ્તામાં આવનાર ભૂમિ	કાદાકીય અને પરંપરાગત જમાન હકો ધરાવનાર તેમજ માલિકો ધરાવનાર પ્રભાવિત વ્યક્તિઓ	૧ નવિની કરણ કરવામાટે થયેલ ખર્ચ માટે વળતર ૨. પુનર્વાસ અને પુનસ્થાપના	૧. એવી જમીન માટે બજાર કિમંત પર રોકડમાં વળતર જે નોટ (ક) (આર.એ.એ. ૨૦૦૮ ની ધારા ૨૦જી) મુજબ નિર્ધારિત કરવામાં આવશે. બજાર કિમંત **આપવામાં આવશે.** ૨. ઉપરોક્ત (૧) આર.એ.એ. ૨૦૦૮ ની ધારા ૨૦ એફ (૯) માં નિર્ધારિત વળતર પર ૬૦ ટકા સોલિશિયમ. ૩. આર.એ.એ. ૨૦૦૮માં નિર્દેશીત જોગવાઈ પ્રમાણે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયુક્ત સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જમીનના વળતર સંબંધી રાજ્ય સરકારના જાહેરનામાં દ્વારા પ્રસિદ્ધ જોગવાઈ પ્રમાણે યોગ્ય પ્રક્રિયા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ વળતરની રકમને ઉપરોક્ત ૧ અને ૨ માટે સ્વીકારવામાં આવશે. ૪. વધારાનું વળતર, રકમ ૨૦,૦૦૦/-રૂપિયા ૧૫૦૦ ચો.મી. સુધી ના સંપદન માટે અને ૧૫૦૦ ચો.મી. થી ઉપર વધુ સંપદન માટે પેરા ૭.૧૯ RRP2007 , અનુસાર રૂપિયા ૧૫ પ્રતિ ચો.મી. ના દર થી સંપાદનની ચુકવણી થશે ૫. જમીન સંપાદન થી જો જમીનવાળા ખેડૂત જમીન વગરના બનીજાય છે અથવા નાના તેમજ સીમાન્ત ખેડૂત ની શ્રેણીમા આવી જાય છે, તો તે પુનસ્થાપન સહાયતાના રૂપમાં ૭૫૦ દિવસ નો કૃષિ વેતન મળવા ને પાત્ર છે. ૬. સંદેહ/વિવાદના કિસ્સા માં સક્ષમ પ્રાધિકારીના વળતર નક્કી કર્યા પહેલા કોઈ સ્વતંત્ર મુલ્યાંકનકર્તાની મદદ લઈ શકે છે. આ સંદર્ભના સંબધિત વિસ્તૃત પ્રક્રિયા નોટ બી માં દર્શાવેલ છે. ૭. સંપાદિત/ બાકીરહેલ ભૂમિ માટે ની વળતરની નીતિ નોટ સી અનુસાર કરવામાં આવશે. ૮. સ્થાપન ભૂમિ માટે કરવામાં આવનાર દસ્તાવેજો નુ રજીસ્ટ્રેશન ખર્ચ તેમજ સ્ટેમ્પ ડ્યુટિ પરિયોજના દ્વારા પાછી(રિફન્ડ) આપવામાં આવશે. આર.એ.એ.૨૦૦૮ ની ધારા ૨૦ (એચ) મુજબ પુનઃવાસ માટેની ભૂમિ પ્રભાવિત પરિવારોને આપવામાં આવેલ વળતરના એક વર્ષ માં ખરીદવામાં આવશે.
૨		નોંધાયેલ ભાડુઆત, કોન્ટ્રાક્ટરો તેમજ ભાડાપટ્ટા ધારકો	બજાર કિમંત થી ખેતર માં ઊભા પાક ના નુકશાન નું વળતર	માન્યતા પ્રાપ્ત ભાડુઆત, કોન્ટ્રાકર તેમજ પટ્ટા ધારકો ભૂમિના વળતર માટે યોગ્ય વ્યક્તિઓ નથી. તેઓને વળતર માટે ત્યારે યોગ્ય ગણવામાં આવશે, કે જ્યારે ઊભા પાક માટે (કાર્યન્વયન સંસ્થા)ઈએ દ્વારા ૩ મહિના પહેલા નોટિસ આપેલ ન હોય.
૩		માન્યતા પ્રાપ્ત નથી તેવા ભાડુઆત, કેન્ટ્રાક દ્વારા ખેતી કરનાર ખેડૂતો, પટ્ટા ધારકો, સેયર કોપર્શ	બજારકિમંત થી ખેતર માં ઊભા પાક ના નુકશાન નું વળતર	માન્યતા પ્રાપ્ત નથી તેવા ભાડુઆત, કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ખેતી કરનારખેડૂતો, પટ્ટા ધારકો, ખેત ભાગીદાર જમીન વળતર માટે હકકદાર નથી, તે ખેતરમાં ઊભા પાક ના વળતર માટે ત્યારેજ હકકદાર છે જ્યારે તેઓને ઈએ દ્વારા ૩ મહિની નોટિસ આપવામાં આવી ન હોય. પાક ભાગીદાર (સેયર ક્રોપર્શ) ના મામલામાં પાકની વળતર માટે જમીનના માલિકો અને પાક ભાગીદાર વચ્ચે સમજુતિ થયાના પ્રમાણમાં રહેશે.
(ખ) પ્રાઈવેટ ઢાંચાઓની નુકશાની (રહેણાંક / **વ્યવસાય માટે**)				
૪	પરિયોજના ના રસ્તામાં આવનાર માળખાંઓ	માલિકી ધરાવનાર	નવિની કરણ કરવા માટે થયેલ ખર્ચ માટે વળતર તેમજ પુનર્વાસ અને પુનર્થાપનાની સહાયતા.	૧. સ્ટ્રકચર(માળખા)ના વિસ્થાપન પર થયેલ ખર્ચનું વળતર, જે નોટ-ડી અનુસાર નક્કિ કરવામાં આવે તે. ૨. તોડવામા આવેલ માળખા માના કાટમાળ /સામગ્રીનો અધિકાર. ૩. મકાનો/ઢાંચાઓને ખાલી કરાવવા માટે ત્રણ મહિનાની નોટિસ ૪. ઉપર મુજબ નિર્ધારિત કરવામા આવેલ બજાર કિમંતના દર પર નવા વૈકલ્પિક મકાનો/દુકાનો ની ખરીદીપર માટે સ્ટેમ્પ ડ્યુટિ અને દસ્તાવેજો માટે થયેલા ખર્ચ નો રિફન્ડ. વૈકલ્પિક મકાનો/દુકાનો આર. એ.એ.૨૦૦૮ ની ધારા ૨૦ (એચ) મુજબ પ્રભાવિત પરિવારોને આપવામાં આવેલ વળતરના એક વર્ષ માં ખરીદવાના રહેશે. ૫. પુનર્વાસ અને પુનર્સ્થાપન સહાય નીચે મુજબ લાગુ કરવામાં આવશે. i) રૂપિયા ૪૦૦૦ /- ની દરેક પરિવારને સહાય. ii) પ્રત્યેક વિસ્થાપિત/પ્રભાવિત પરીવારને સ્થળાંતર માટે એક વખત માટે રૂપિયા ૧૦,૦૦૦/- ની નાણાંકીય સહાય ની જોગવાઈ (એન.આર.આર.પી.૨૦૦૭, પેરા ૭.૧૦) iii) પ્રત્યેક પ્રભાવિત પરિવારો કે જેમની પાસે પશુ છે તેઓને વિસ્થાપન થયા પછી પશુઓ માટે કે તેઓના પશુઓની ગમાણ માટેની વ્યવસ્થા માટે વિત્તિય/નાણાકીય સહાયના રુપમાં રૂપિયા ૧૫૦૦૦/- ની સહાય. (એન.આર.આર.પી.૨૦૦૭, પેરા ૭.૧૦) iv) પ્રત્યેક પ્રભાવિત વ્યક્તિ, જે **ગ્રામીણ કારીગર,** ગામમાં નાનો રોજગાર **અથવા** સ્વરોજગાર ધરાવતો વ્યક્તિ છે અને જો તેને વિસ્થાપિત થવુ પડે તો તેને વર્કિન્ગ શેડ તેમજ દુકાનના નિર્માણ માટે રૂપિયા ૨૫,૦૦૦/- ની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. (એન.આર.આર.પી.૨૦૦૭, પૈરા ૭.૧૨) v) ગરીબી રેખા નીચે જીવતા ગ્રામ્ય વિસ્તારના અસરગ્રસ્તોને ઈન્દિરા આવાસ યોજના પ્રમાણે ની અદ્યતન(વર્તમાન) નિર્માણખર્ચ પ્રમાણેની આર્થિક સહાયતા આપવામાં આવશે. તેમજ શહેરી અસરગ્રસ્તોને જે.એન.યુ.આર. એમ. **અનુસાર થતા નિર્માણ ખર્ચ** પ્રમાણેની કિંમત મુજબ મકાન બાંધકામ માટે ની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે.
૫	પરિયોજના ના રસ્તા માં આવનાર માળખાઓ	ભાડુઆત/પટ્ટાધારકો	પુનર્સ્થાપના અને પુનર્વાસ સહાયતા.	૧.રજીસ્ટર્ડ પટ્ટાધારી સ્થાનિક કાયદા મુજબ માળખાના માલિક ને આપવામાં આવેલ વળતર માં ભાગિદાર ગણાશે. ૨. ભાડેથી રહેનાર ની બાબતમાં મહિના ૧૦,૦૦૦/-રૂપિયા સ્થાળાંતર ના ભથ્થા **રૂપે આપવા માં આવશે . સ્ટ્રક્ચર ખાલી કરવા ૩ મહિના ની લેખિત નોટિસ આપવી. જો નોટિસ ન આપી હોય તો ત્રણ મહિનાનુ ભાડુ નોટિસના બદલામાં આપવામાં આવશે.**
ગ). વૃક્ષો અને પાકની નુકશાની				
૬	પરિયોજના ના રસ્તા માં આવનાર ઊભા વૃક્ષો અને ખેતર માં ઊભા પાક	ભૂમિના માલિકો અને હિતબદ્ધ વ્યક્તિ	બજાર કિમંત મુજબ વળતર	૧. ફળો, ઊભા પાકોને લણવા વૃક્ષોને કાપવાથી પ્રભાવિત વ્યક્તિઓ ને ૩ મહિના આગળથી નોટિસ આપવામાં આવશે. ૨. આ નુકશાનીનું વળતર નીચેના વિભાગો દ્વારા અંદાજીત કર્યા મુજબ આપવામાં આવશે. i) વૃક્ષો તેમજ લાકડા માટે - વન વિભાગ ii) પાક તેમજ ફળો માટે - રાજકીય કૃષિ વિભાગ

				iii) પેરેનિયલ (સદાબહાર) વૃક્ષોમાટે - હોર્ટિકલ્ચર વિભાગ iv) વૃક્ષો, પાક અને બાગયતી પાક ની નુકશાની માટે માલિકો ઉપરાંત દરજ્જા વગર રહેતા લોકોને બજાર કિમંત પર વળતર આપવામાં આવશે.
૫). અનધિકૃત લોકો દ્વારા રહેણાંક તેમજ કામકાજ ના મળખાં ને થતી નુકશાની				
	પરિયોજના ના રસ્તા માં આવનાર માળખાં	અધિસુચના (૨૦એ) દરમિયાન જાણવામાં આવેલ માળખાંના માલિકો	નવિની કરણ કરવામાટે થયેલ લાગત માટે વળતર પુનર્વાસ અને પુનર્સ્થાપન સહાયત.	૧.અનધિકૃત તેમજ દરજ્જા વગર રહેતા લોકો (જે નોટ એફ માં દર્શાવેલ છે.) ને ત્રણ મહિના ની નોટિસ આપવામાં આવશે, અને પાકો તેમજ માળખાંની નુકશાની માટે વળતર આપવામાં આવશે. **૨. સ્ક્વેટર્સ (નોટ-F માં આપેલ વ્યાખ્યા અનુસાર)ને આર્થીક સહાય રૂપે તેમના સ્ટ્રક્ચર નુ વિસ્થાપન ખર્ચ નોટ-D માં દર્શાવ્યા અનુસાર આપવામાં આવશે.** i) ૪૦૦૦/-રૂપિયા પ્રત્યેક પ્રભાવિત પરિવારો ને સ્થળાંતરભથ્થા તરીકે ii) ૧૦,૦૦૦/- રૂપિયાપ્રત્યેક પ્રભાવિત પરિવારો વિસ્થાપન હેતુ સ્થળાંતર માટે ની જોગવાઈ ના ભથ્થા તરીકે (પૈરા ૭.૧૧ એન.આર.આર.પી. ૨૦૦૭) iii) પશુઓ માટે કે તેઓના રહેણાંક ની હાનિમાટે ૧૫,૦૦૦/- રૂપિયા ની સહાય (પૈરા ૭.૧૦ એન.આર.આર.પી. ૨૦૦૭) iv) પ્રત્યેક પ્રભાવિત વ્યક્તિ, **જે ગ્રામીણ કારીગર,** ગામમાં નાનો રોજગાર અથવા સ્વરોજગાર ધરાવતો વ્યક્તિ છે અને જો તેને વિસ્થાપિત થવુ પડે તો તેને વર્કિન્ગ શેડ તેમજ દુકાનના નિર્માણ માટે રૂપિયા ૨૫,૦૦૦/- ની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. (એન.આર.આર.પી.૨૦૦૭, પૈરા ૭.૧૨) v) ગરીબી રેખા નીચે જીવતા ગ્રામ્ય વિસ્તારના અસરગ્રસ્તોને ઈન્દિરા આવાસ યોજના પ્રમાણે ની અદ્યતન(વર્તમાન) **નિર્માણખર્ચ** પ્રમાણેની આર્થિક સહાયતા આપવામાં આવશે. **તેમજ** શહેરી અસરગ્રસ્તોને જે.એન.યુ.આર. એમ. **અનુસાર થતા નિર્માણ ખર્ચ** પ્રમાણેની કિમત મુજબ મકાન બાંધકામ માટે ની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે.
૬). આજીવિકા પર થતુ નુકશાન				
૮.	પરિયોજના ના રસ્તામાં આવનાર પરિવારો	માલિકી/ગૈર માલિકી/પાક ભાગીદાર/ભૂમિ મજૂરો, નોકરી કરનાર લોકો	પુનર્વાસ સહાયતા	૧.આજીવિકા ગુમાવનાર પરિવારોને પુનર્વાસ સહાયતા રૂપે ૭૫૦ **દિવસ ની ન્યુનતમ ખેત મજૂરી આપવામાં આવશે.** (એન.આર.આર.પી. ૨૦૦૭, પૈરા. ૭.૧૪) **જમીન માલિકો જેઓ ઉપરોક્ત સેકશન ૧(૫)અંર્તગત સહાયતા પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓને આ સહાયતા મળવાને પાત્ર નથી.** ૨. તાલિમ મેળવવા માટે પ્રત્યેક પરિવાર દિઠ ૪૦૦૦/-રૂપિયા ની સહાયતા. ૩. પરિયોજના ના નિર્માણ દરમિયાન જ્યાં સુધી શક્ય છે ત્યાં સુધી પરિયોજના ના કોન્ટ્રક્ટરો દ્વારા પ્રભાવિત પરિવારો ખાસ કરીને ગરીબી રેખાનીચે આવનાર (બી.પી.એલ.) પરિવારના લોકોને નિર્માણ કાર્ય માં હંગામી રોજગારી આપવી.
ચ. ૧). નબળા વર્ગ(**વલ્નરેબલ ગ્રુપ**)(નોટ-ઈ માં બતાવ્યા મુજબ) અને ગરીબી રેખા નીચે જીવન ગુજારનાર લોકો માટે **વધારાની** સહાયતા				
૯	પરિયોજના ના રસ્તામાં આવનાર પરિવારો	પરિયોજના ના રસ્તામાં આવનાર પરિવારો.	પુનર્વાસ અને પુનર્સ્થાપના ની સહાયતા	એક વખત માટે વધારેમાં વળતર માટે ઓછા માંઓછી ૩૦૦ દિવસ બરાબર ની મજુરી ની જોગવાઈ. મુજબ ૩૦૦ ની ન્યુનતમ વેતનની ની શક્યતા મેળવતા બી.પી.એલ. પરિવારો આ સહાયતા નો લાભ લઈ શકે નહી.
ચ ૨). અનુસુચિત જન જાતિના પ્રભાવિત પરિવારોને વધુમાં સહાયતા				
૭ ૧૦	પ્રભાવિત અનુસુચિત	પરિયોજનાના રસ્તામાં આવનાર પરિવારો.	પુનર્વાસ સહાયતા	૧.પરંપરાગત અધિકારો તેમજ વન ઉત્પાદન મેળવવાના હક્ક ની **હાનિ** માટે અનુસુચિત જન જાતિ ના પ્રભાવિત પરિવારોને ખેત

	જનજાતિના પરિવારો			મજૂરીના ઓછા માં ઓછા ૫૦૦ દિવસના વેતન બરાબર એક વખત માટે વધુ વળતર આપવામાં આવશે (પૈરા ૭.૨૧.૫ એન.આરઆર.પી ૨૦૦૭) ૨. જમીન સંપાદન ના કિસ્સામાં પ્રત્યેક અનુસુચિત જન જાતિના પ્રભાવિત પરિવારોને નુકશાની ના વળતરની રકમ માંથી ત્રીજા ભાગ ની રકમ પહેલા હપ્તાના રુપમાં શરુઆતમાં આપવામાં આવશે, જ્યારે બાકી રકમ જમીનનો કબ્જો લેતી વખતે આપવામાં આવશે. (પૈરા ૭. ૨૧. ૪ એન.આરઆર.પી ૨૦૦૭)
છ). સામુદાયિક સંપત્તિ ,સંસાધનો ને થતું નુકશાન				
૧૧	પરિયોજના માર્ગમાં ઢાંચાઓ અને અન્ય સંશાધનો (જેમ કે જમીન, પાણી, સામાજિક સેવાઓ)	પ્રભાવિત સમુદાય અને સમુહ	સામુદાયિક માળખાં અને સામુહિક સંપત્તિ, સંસાધનોનું પુનઃ નિર્માણ	સમુદાય સાથે વાતચીત કરીને જે ઉચિત હશે તે મુજબ સામુહિક સંપત્તિ સંસાધનોને પુનઃનિર્માણ અને પુનઃ સ્થાપિત કરવા.
જ). નિર્માણ સમયે હંગામી રીતે અસર				
૧૨	નિર્માણ સમયે ભૂમિ અને સંપત્તિને થતું નુકશાન	ભુમિ **અને અસ્થાઈ** સંપત્તિ ના માલિકો	નિર્માણ સમયે અસ્થાયી પ્રભાવ માટે નુકશાની જેમકે સાધનોની અવરજવર, ભારે મિશિનરીઓ અને પ્લાન્ટ સ્થળ ના સંચાલન ના કારણે જમીન સંપત્તિનું નુકશાન	નિર્માણ સમય દરમિયાન મશિનરીઓ ના સંચાલન તેમજ નિર્માણ પ્લાન્ટ ની સ્થાપના ને કારણે માળખાં તેમજ જમીન પર પ્રભાવની નુકશાની નું વળતર કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આપવામાં આવશે. પ્રસ્તાવિત માર્ગ ની બાજુ ની જમીન અસ્થાયી ઉપયોગ માટે ભૂમિ માલિકો અને કોન્ટ્રાક્ટરો વચ્ચે લેખિત માં અનુમોદન હોવુ જોઈએ. કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા **નિર્માણ** સ્થળોની સ્થાપના ડી.એફસી.સી.આ.એલ. નીસલાહ લઈને કરીને કરવામાં આવશે.

<u>નોટ-એ</u>

૧ સક્ષમ પ્રાધિકારી દ્વારા વળતરનું નિર્ધારણ આર.એ.એ. ૨૦૦૮ ધારા ૨૦ જી માં આપવામાં આવેલ જોગવાઈઓ અનુસાર આપવામાં આવશે, જે જમીન ની બજાર કિમંત નિરધારણ કરવા માટે નિમ્નલિખિત માપ દંડોનો ઉલ્લેખ કરે છેઃ-

i)ઓછામાં ઓછી જમીન કિમંત જે કોઈ, ક્ષેત્રમાં વેચાણ દસ્તાવેજો માટે ભારતીય સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૮૯૯માં ઉલ્લેખિત, જ્યાં જમીન સ્થિત હોય, અથવા

ii) ગામ અથવા તો તેની હદમાં આવેલ એ જ **સમાન** પ્રકારની જમીનની સરેરાશ વેચાણ કિમંત, કે જેની ખાત્રી છેલ્લા ૩ વર્ષમાં નોંધાયેલ દસ્તાવેજ પૈકી, **ઓછામા ઓછા** પચાસ ટકા **ઉંચી કિમતના દસ્તાવેજો,** તેના અધારે કરવામાં આવશે.

૨. જ્યાં ઉપર્યુક્ત જોગવાઈ લાગુ નથી પડતી ત્યાં રાજ્ય સરકર તે જમીન માટેની તળીયાની કિમંત આસ-પાસ ના વિસ્તારમાં તે પ્રકારની જમીનની સરેરાશ કિમંત આધારે નિયત કરશે, જે છેલ્લા ૩ વર્ષો દરમિયાન વેચાણ દસ્તાવેજોના ઉંચી કિમંતના ૫૦% દસ્તાવેજોને ધ્યાનમાં રાખીને સક્ષમ અધિકારી તે મુજબ જમીન ની કિમંત નક્કિ કરશે (આ.એ.એ. ૨૦૦૮ ની ધારા ૨૦ જી નું પાલન કરવામાં આવશે).

૩. વળતરની રકમ નિયત કરતી વખતે સક્ષમ અધિકરી તેમજ **મધ્યસ્થિએ/લવાદે** આર.એ.એ. ૨૦૦૮ ની ધારા ૨૦ એફ(૮) માં આપવામાં આવેલ પ્રાવધાનો અનુસાર બાબતોનું ધ્યાન આપવામાં આવશે.

i) ભૂમિપર કબ્જો મેળવતી વખતે હિતધરાવનાર વ્યક્તિઓને કોઈ નુકશાન થયું હોય, જમીન ના અન્ય જમીનો થી ભાગલા પડવાના કારણે થયું હોય

ii) ભૂમિપર કબજો મેળવતી વખતે હિતધરાવનાર વ્યક્તિઓને કોઈ નુકશાન થયુ હોય જેના કારણે તેઓની અન્ય અચલ સંપત્તિ અથવા તેમની આવકમાં કોઈપણ પ્રકારે પ્રભાવિત થઈ હોય.

iii) જો જમીન સંપાદનના કારણે હિતધરાવનાર ને તેઓના નિવાસ તેમજ ધંધાના સ્થાનો બદલવા મજબુર થાય છે તો આવા સંજોગોમાં તે ખર્ચ અંગેનું આનુવંશિક વ્યાજબી ખર્ચ.

૪. સંપાદન કરવામાં આવનાર જમીનની બજાર કિમંત નિર્ધારણ કરતા પહેલા સક્ષમ અધિકારી નિમ્નલિખિત માહિતી માગશે.

i) આવી ભૂમિ નો ઉપયોગ તેમજ તેના પ્રકાર જાણવા.

ii) આજુ બાજુ ના ક્ષેત્રમાં આ પ્રકારની જમીન ની કિમંત તેમજ શ્રેણી જાણવી.

૫. કોઈ વ્યક્તિજો તે ભૂમિ તેમજ સંપત્તિનો ઉપયોગ કરતો હોય અને જો ને ભૂમિ /સંપત્તિ ને સંપાદિત કરવામાં આવે છે તો તેની ક્ષતિ પૂર્તિ માટે આર.એ.એ. ૨૦૦૮ ની ધારા ૨૦ એફ(૧) મુજબ નિર્ધારણ કરવામાં આવેલ વળતરના ૧૦ ટકા રકમનું ચુકવણું ઈએ દ્વારા માલિક અને અન્ય વ્યક્તિ જે ભૂમિનો ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિ /પરિવાર છે તેને આપવામાં આવશે, ઊપર મર્યાદિત હક્ક ધરાવતો હોય.

<u>નોટ-બી</u>

ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ. સરકાર **માન્ય એવા સ્વતંત્ર મુલ્યાંકન કર્તાની** નિમણુક કરશે કે જે નીચે બતાવેલ પરિબળોના મુલ્યાંકન કરવા માટે જરુરી માહિતી અને સહાય સક્ષમ અધિકારીને જણાવશે.

i) તાજેતરના વેચાણકરેલ દસ્તાવેજો નુ મુલ્યાંકન કરવું તેમજ **આજુ બાજુ માં, ગ્રામ્ય અથવા શહેરી ક્ષેત્ર માં આવેલ સમાન પ્રકારની જમીનના તાજેતરના વેચાણ દસ્તાવેજ, ભુમિમાલીકી ટ્રાંસફર કરાર અને દસ્તાવેજ પ્રમાણ પત્રો નુ મુલ્યાંકન કરવું.**

ii) જિલ્લાના શહેરી તેમજ ગ્રામીણ ક્ષેત્ર ના સર્કલ ભાવ નક્કિ કરવા.

iii) ૨૦ વર્ષ સુધીની ભૂમિની કૃષિ ઉત્પાદકતા નક્કિ કરવી.

<u>નોટ-સી</u>

જો બાકી બચતા પ્લોટો જે આર્થિક રીતે ઉપયુક્ત નથી તો ઈએ રાજ્યમાં લાગુ કાયદાઓ તેમજ ઉપધારાઓ નું પાલન કરીને તે અનુસાર ક્ષતિપૂર્તિ કરશે. જો ઈએ ની ખરીદી બાદ તે જિલ્લા માં રહેલ ભૂમિ ની સરેરાશ કરત. ઓછી થઈ જાય છે અને આ સંદર્ભ માં રાજ્ય ની ધારાઓ અને ઉપધરાઓ સ્પષ્ટ નથી તો પ્રભાવિત પક્ષકારો ની સાથે કરાર કરતી વખતે નીચે માંથી કોઈ એક નિયમ નુ પાલન કરવામાં આવશે.

i)EA, દર્શાવેલ "હક્કની પાત્રતા"(entitlement matrix) ના નિયમો નું પાલન કરતા પરિયોજના માટે સંપાદન કરાયેલ ભૂમિની બાકી રહેતી ભૂમિ નું સંપાદન કરશે.

ii)EA દ્વારા પ્રભાવિત પક્ષકારો ને જે બાકી પડીરહેલ જમીનની પ્રતિકુળતા માટે ૨૫ ટકા વળતર પ્રભાવિત પક્ષકારો ને જમીન ખરીદયા વગર આપવામાં આવશે.

<u>નોટ-ડી</u>

મકાનો, ભવનો તથા અન્ય અચલ સંપત્તિ તુ વળતર માટે વળતર નું નિર્ધારણ ઘસારાં વગર દરો ની મુળભૂત **સુનિશ્ચિત દર** ધ્યાને લઇ **વિસ્થાપન (ઘસારા વગર)** માટે થયેલ ખર્ચના આધાર પર કરવામાં આવશે. આધારભૂત સૂચિ ના દર નક્કિ કરતી વખતે સરકાર માન્ય એક સ્વતંત્ર **મૂલ્યાંકન કર્તા** ને રાખીને શહેર તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારોના રહેણાંક તેમજ ધંધાના માળખાઓ માટે ના છેલ્લા માં છેલ્લા મુળભૂત **સુનિશ્ચિત દર** ને માલિકો સાથે પરામર્શ કરીને અમલમાં લેશે.

<u>નોટ-ઈ</u>

NRRP 2007 અસુરક્ષિત(વલનેરેબલ) વ્યક્તિઓ ની પરિભાષા બતાવે છે, વિકલાંગ આશ્રય વિનાના, અનાથ, વિધવા, અવિવાહિત સ્ત્રીઓ, ત્યક્તા મહિલાઓ યા એવી વ્યક્તિઓ કે જેમની ઉંમર ૫૦ વર્ષ થી વધુ છે, જેઓને વૈકલ્પિક આજીવિકા ઉપલબ્ધ નથી અને જેઓ ને કોઈ પરિવાર નથી તેઓ ને પરિભાષિત કરવામાં આવ્યાછે. (પેરા ૬.૪(૫) **NRRP 2007**)

<u>નોટ-એફ</u>

વ્યાખ્યા

<u>-સીમાંત ખેડુતઃ</u>

સીમાંત ખેડૂત એવો ખેડૂત કે, જેની પાસે એક હેક્ટર બિન પિયત અથવા અડધા હેક્ટર જેટલી પિયત જમીન હોય.

<u>-નાનો ખેડુતઃ</u>

નાનો ખેડૂત એવો ખેડૂત કે, જેની પાસે બે હેક્ટર બિન પિયત જેટલી જમીન હોય અથવા તો એક હેક્ટર થી વધારે પિયત જમીનપરંતુ સીમાંત ખેડૂત કરતા વધારે જમીન હોય.

<u>-દબાણ કર્તાઓઃ</u>

કોઈ એવી વ્યક્તિ/પરિવાર સાર્વજનિક ભૂમિ માં કબ્જો કર્યો છે (નિયત તારીખ પહેલા) તથા પોતાનુ આશ્રય સ્થાન તેમજ પોતાની આજીવિકા નું ગુજરાન ચલાવતો હોય .

<u>અનાધિકૃત દબાણકર્તા (squatter)</u>

કોઈ એવી વ્યક્તિ/પરિવાર જે કોઈની અનુમતિ વગર સાર્વજનિક ભૂમિપર રહેછે, તેમજ નિયત તારીખ પહેલા કોઈ અધિકાર વગર સાર્વજનિક ભવનો નો ઉપયોગ કરે છે અને તેના આશ્રય/જીવન નિર્વાહ માટે બીજો કોઈ સ્ત્રોત નથી.

મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય માટે સરકારી ઠરાવ :-

1. મહારાષ્ટ્ર સરકાર, ડી. એફ.સીસી માટે સંપાદિત થતી પ્રાઈવેટ ભૂમિનું વળતર નકકી કરવામાટે (સરકારી ઠરાવ) પસાર કર્યું છે. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય માં ડીએફસીસી માટે સંપાદિત થતી ભૂમિનું નિશ્ચીત કરવા, કલેક્ટર શ્રી(ચેરમેન), ભૂમિસંપાદન અધિકારી/સક્ષમપ્રાધિકારી (સભ્ય સેક્રેટરી) અને સાથે પાંચ સભ્યોની એક સમિતિ બનાવવામાં આવશે.
2. જમીન ની કિંમત નકકી કરવા સમિતિ "એન્ટાઈટલમેંટ મેટ્રીક્સ" નોટ **A**, આર.આર.એ. ૨૦૦૮ નું પેરા ૨૦જી, પી.એ.પી.(પરિયોજના પરિણામ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ) ના દાવા, જોઈન્ટ મેજરમેંટ સર્વેના લેંડમાર્કેટ સર્વે નો રિપોર્ટ અને નજીકના ક્ષેત્રનો વિકાસ પામતા અને બીજા વિષયલક્ષી. જમીન ની કિંમતથી સંબંધિત બીજા સ્થાનિક પરિબળો ધ્યાનમાં લેશે.
3. સમિતિ કિંમત નાપ તૈયાર કોઠો(રેડી રેકનર) ને એજ સમયના વેચાણ દસ્તાવેજ સાથે સરખાવશે અને જમીન માલિકને ઉચી કિંમત આપશે. જો જમીન માલિક આ કિંમતથી સહમતન હોય તો સમિતિ ગ્રામવાસીઓને મંજુર કિંમત નિશ્ચીત કરી શકશે અને લોક સંપાદન સંસ્થાની મંજુરી (આપરહવઅલ) માટે લેખિત ભલામણ મોકલશે અને પછી સમિતિ કિંમત ફાઈનલ કરશે.
4. સમિતિ કિંમત નકકી કરવા મહીનામાં એકવાર ચોકસ પણે સભા કરશે. સમિતિ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનાં, એ ગામો જેમાં ડી.એફ.સી.સી એ ભૂમીસંપાદન નું આયોજન કર્યું છે, સમિતિ સંપાદનમાટે વળતરની કિંમત નકકી કરી, વળતરની વહેંચણી કરવા તેને જાણ સક્ષમપ્રાધિકારી ને કરશે.

સંસ્થાકિય વ્યવસ્થા:

પ્રાયોજના અમલીકરણ સંસ્થા તરીકે ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ યોજનાના સમગ્ર તાંત્રિક પાસાંઓ અને અમલ માટે જવાબદાર છે અને સમગ્ર અમલીકરણની પ્રક્રિયા તથા ધીરણના નાણાંના ઉપયોગની દેખભાળ કરશે. સંસ્થાના વડા તરીકે ડી.એફ.સી.સી.આઈ. એલ દ્વારા વડોદરા, સુરત, મુંબઈ અને નોઈડા ખાતે પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ યુનિટ (**PMU**) તરીકે કામ કરવા મુખ્ય પ્રોજેક્ટ મેનેજરના કાર્યલય (**SEMU**) ની રચના કરી દેવાઈ છે જેનું નેતૃત્વ જનરલ મેનેજર કક્ષાના અધિકારી કરે છે - જે જમીન સંપાદન, પુર્વાસ તથા પુનઃસ્થાપન પ્રક્રિયાનું ધ્યાન રાખશે.

મુખ્ય કાર્યાલય તથા પ્રોજેક્ટ ઓફિસનું વહિવટી/સંસ્થાકીય માળખું નીચે આકૃતિ ૧ અને ૨ માં આપેલ છે.

	પ્રવૃત્તિ	૨૦૧૦		૨૦૧૧				૨૦૧૨				૨૦૧૩				૨૦૧૪			
		૧	૨	૧	૨	૩	૪	૧	૨	૩	૪	૧	૨	૩	૪	૧	૨	૩	૪
૧	જમીન આયોજન તૈયારી	■	■	■	■														
૨	RRA-૨૦૦૮ નું ૨૦A જાહેરનામું	■	■	■	■														
૩	વાંધાઓની સુનાવણી	■	■	■	■	■													
૪	જમીન માલીકની ઓળખ	■	■	■	■	■													
૫	RRA-૨૦૦૮ નું ૨૦A જાહેરનામું	■	■	■	■	■													
૬	સંયુક્ત તપાસ (સંયુક્ત માપન સર્વેક્ષણ)	■	■	■	■	■	■												
૭	પાયાનું સર્વેક્ષણ તથા વસતી ગણતરી	■	■	■	■	■													
૮	સૂચિત RRP ને તૈયાર કરવો				■	■	■												
૯	સૂચિત RRP માટે લોક સંવાદ બેઠકો				■	■	■												
૧૦	સૂચિત RRP ની ઘોષણા				■	■	■												
૧૧	કલમ હુકક ધરાવનાર અંગુઠાનું અંતિમ સ્વરુપ					■	■												
૧૨	અંતિમ RRP ની તૈયારી						■												
૧૩	અંતિમ RRP ની ઘોષણા						■												
૧૪	જમીન, પુનસ્થાપન અને પુનવાસ માટે પળતરની તૈયારી	■	■	■	■	■	■	■	■										
૧૫	સક્ષમ અધિકારી પાસે નાણાં જમા કરવા	■	■	■	■	■	■	■	■										
૧૬	અસરગ્રસ્તોને નાણાંની વહેંચણી	■	■	■	■	■	■	■	■										
૧૭	જમીનનો કબજો મેળવવા	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
૧૮	કાર્યનો પ્રારંભ અમલ									■	■	■							
૧૯	પુનર્વાસની અસરનું મોનીટરીંગ દેખરેખ										■	■	■	■	■	■	■	■	■
૨૦	RRPની અસરકારક્તા દેખરેખ (આંતરીક)							■	■	■	■	■	■	■	■	■			
૨૧	RRPની અસરકારક્તા દેખરેખ (બાહ્ય)								■		■		■		■				
૨૨	વિવાદોની પતાવટ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

જરુર જણાશો તો વધારાની લોક સંવાદ બેઠકો કરાશે.
સંબંધિત જમીન સંપાદનની પૂર્તિ બાદ જ અમલીકરણ કાર્ય થશે.

પુનઃસ્થાપન સમયપત્રક આપવું.

ફરીયાદ નિવારવાની પદ્ધતિ

RRP૨૦૦૭ ની કલમ ૮.૧ પ્રમાણે મુખ્ય અને ક્ષેત્રિય કક્ષાએ યોજના અસરગ્રસ્ત લોકો અને પરિવારો માટે તથા ડી.એફ.સી પ્રોજેક્ટ ના અમલીકરણની પ્રક્રિયામાં હિતધારક સ્થાનિક નિવાસીની ફરીયાદ સાંભળવા અને નિવારણ કરવા પૂનર્વાસ અને પુનઃસ્થાપન સમિતિની રચના કરવામાં આવશે.

(૧)ક્ષેત્રિય સ્તરે વિવાદોની પતાવટઃ મુખ્ય પ્રોજેક્ટ મેનેજરના આયોજન હેઠળ પુનર્વાસ અને પુનઃસ્થાપન સમિતિ હશે જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થશે.
અ. જે તે જીલ્લાના કલેક્ટર અથવા તેના પ્રતિનિધી (અધ્યક્ષ) ;
બ. સંબંધિત સક્ષમ અધિકારી /વહિવટકર્તા (**R&R**) આમંત્રિત) ;
ક. સંબંધિત મદદનીશ પ્રોજેક્ટ મેનેજર-સમાજિક (માત્ર કાર્યલય સેવા પુરી પાડવા માટે) ;
ડ. જીલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અથવા તેના પ્રતિનિધિ
ઈ. સામાજિક પ્રતિનીધિ/સ્થાનિક સન્માનનિય બિન સરકારી સંગઠન (સંસ્થા)

(૨) યોજના કક્ષાએ ફરીયાદ નિવરણઃ જનરલ મેનેજર (સેમુઃ **SEMU**) ના આયોજન હેઠળ પુનર્વાસ તથા પુનઃસ્થાપન સમિતિ હશે જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થશે.
અ. ડાયરેક્ટર (માળખું) ;
બ. ડેપ્યૂટી/નાયબ જનરલ મેનેજર-ફરીયાદ;
ક. સામાજિક નિષ્ણાત;
ડ. રેલ્વે મંત્રાલયના પ્રતિનિધી.

(૩) લવાદની ભૂમિકાઃ **RRA**-૨૦૦૮ હેઠળ મળવાપાત્ર વળતર અંગેની યોજના અસરગ્રસ્ત પરિવારોની ફરીયાદના નિવારણ માટે જૂલાઈ ૧૫, ૨૦૧૦ ના ગેઝેટમાં નિયુક્ત કરાયેલ મહેસુલ વિભાગના કમિશ્નર કામ કરશે.

(૪) ડી. એફ.સી.સી. આઈ. એલ દ્વારા નિયુક્ત પુનઃસ્થાપન અને પુનર્વાસ સમિતિ દ્વારા સંતોષ ન સંભળાયેલ વિવાદોની પતાવટ માટે જો અસરગ્રસ્ત લોકો કે પરિવારો વિનંતિ કરશે તો રેલ્વે મંત્રાલય તે માટે તટસ્થ વ્યક્તિની નિમણૂંક કરશે.

ડી. એફ.સી. કોર્પોરેટ સ્તરે ફરીયાદ નિકાલ વ્યવસ્થા

૧. ક્ષેત્રીય કક્ષાએ ફરિયાદ નિકાલ વ્યવસ્થા.

- **i.** ખેતી, નિવાસ કે વ્યવસાયીક અને અન્ય અસ્કયામતોના વળતર અંગેની ફરીયાદો માટે પ્રારંભિક તબક્કામાં મુખ્ય પ્રોજેક્ટ મેનેજર (**CMP**) દ્વારા ઉકેલ લાવવામાં આવશે. જો ક્ષેત્રિય કક્ષાએ ઉકેલ નહીં આવે તો મુખ્ય કાર્યાલયને મોકલાશે.

૨. કોર્પોરેટ કક્ષાએ ફરીયાદ નિકાલ વ્યવસ્થાં

- **i.** ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ દ્વારા પ્રત્યેક પ્રાપ્ત થયેલ ફરીયાદની નોંધણીથી તેની સ્થિતિ અને નિકાલ સુધી દેખરેખ રહે તે પ્રકારની કેન્દ્રીત ફરીયાદ નિવારણ વ્યવસ્થા સ્થાપવામાં આવશે.
- **ii.** રેલ્વે મંત્રાલય તથા **CVC** માર્ગ દર્શિકાઓની જોગવાઈ મુજબ ફરીયાદ નિવારણ વ્યવસ્થા સ્થાપવામાં આવી છે.
- **iii.** દરેક ક્ષેત્રેય કાર્યાલય અને કોર્પોરેટ કાર્યાલયે દરેક **GGM /GM** પાસે ફરીયાદ નોંધણીપત્રક શરુ કરાયું છે લાગતા-વળગતા દરેક અધિકારીને મળતી પ્રત્યેક ફરીયાદ નોંધવામાં આવશે. તપાસ-તકેદારી માંગી લેતી પ્રત્યેક ફરીયાદને સંબંધી અધિકારી દ્વારા **CVO** તરીકે નોંધવામાં આવશે.
- **iv.** મળેલ ફરીયાદના સમાધાન માટે (**GM/IT**) મહાપ્રબંધક સૂચના **પ્રૌધોગિકી** ફરીયાદ નિવારણ મુખ્ય અધિકારી તરીકે નિમવામાં આવ્યા છે જે દર મહિને
  મળેલી ફરીયાદોના નિકાલની સ્થિતિ બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર સમક્ષ રજુ કરશે.
- **v.** ડી.એફ.સી.સી.આઈ. એલ. દ્વારા મળેલ પ્રત્યેક ફરીયાદને સ્વયં સંચાલિત, ચોક્કસ **સંદર્ભિત** અહેવાલના સ્વરુપમાં નોંધી યોગ્ય રીતે નિકાલ માટે કાર્યવાહી કરાશે. **પ્રત્યેક કેસ નો સ્વચાલિત પ્રમાણભુત બંધારણ અહેવાલ પેદા થશે.**
- **vi.** ડી. એફ. સી. સી. ને મળેલ પ્રત્યેક ફરીયાદોનું સમાધાન તેમજ તેના જવાબો ૧૫ દિવસની અંદર અપાશે.
- **vii.** ટીપ્પણીઓ, મંતવ્યો તેમ જ ફરીયાદોને નિવારણ સહિત વેલ સાઈટ http://www.dffccil.org. પર મુકવામાં આવશે. આમાં દરેક મહિને સુધારા કરવામાં આવશે. ફરીયાદ કર્તાઓની ફરીયાદોની સ્થિતિ ઓન લાઈન જાણવા.
- **viii.** તપાસ અને લીધેલા પગલાંઓની સ્થિતિ જાણવા માટે માસિક અહેવાલ તૈયાર કરી મુખ્યાલયે મોકલાશે.
- **ix.** ફરીયાદ વ્યવસ્થાપનની કાર્યક્ષમતા માટે સંબંધીત ફરીયાદોને સુચનાના વિવિધ માધ્યમો-જેવા કે વેબ સાઈટ, કામ-કાજના સ્થળો, અને ક્ષેત્રિય કાર્યલયોના નોટીસ બોર્ડો પર વિસ્તારથી પ્રકાશીત કરવામાં આવશે.

ખર્ચનો અંદાજ:

ફેઝ ૨ ના **RRP** ને અંતિમ રુપ અપાયા બાદ ખર્ચનો અંદાજ તૈયાર કરાશે.

પુનર્વાસ તથા પુનઃસ્થાપન અહેવાલનું વિતરણઃ

પુનર્વાસ તથા પુનઃસ્થાપન આયોજન અંગેની વિગતવારમાહિતી નીચે જણાવેલ સ્થળે જાહેર કરવામાં આવશે.

-સ્થાનિક ભાષામાં (હિન્દી, મરાઠી કે ગુજરાતી) દરેક અસરગ્રસ્ત ગામે આ સાર અહેવાલ પ્રગત થશે.

-સમગ્ર અહેવાલ અંગ્રેજીમાં સંબંધિત મુખ્ય પ્રોજેક્ટ મેનેજરના કાર્યાલયોએ ડી.એફ.સી.સી.આઈ.એલ.ના મુખ્ય કાર્યલયે, મહત્વના રેલ્વે સ્ટેશનોએ અને જીલ્લા કલેક્ટર કચેરીએથી ઉપલબ્ધ થશે.

સંબંધિત સંસ્થાઓનો સંપર્ક

CPM કાર્યલય મુંબઈ: ૭મા માળે, નવું વહીવટી મકાન, સેન્ટ્રલ રેલ્વે, ડી.એન.રોડ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧

CPM કાર્યલય સુરતઃ ૪ થે માળ અરુંશ-૧, ઈસ્કોન મોલ પાસે,ડુમસ રોડ,પીપલોદ, સુરત-૩૯૫૦૦૭

CPM કાર્યલય વડોદરાઃ ૧૩-૧૪, ૧૭-૧૮, પેનોરમા કોમ્પ્લેક્ષ, ત્રીજોમાળ, આર. સી. દત્ત રોડ, અલ્કાપુરી, વડોદરા.

CPM કાર્યલય નોયડાઃ સ્ટાર હાઉસ, પહેલો માળ, એ -૧૦૨, સેક્ટર-૪, નોયડા, ઉત્તર પ્રદેશ.

સક્ષમ પ્રાધિકારી ઓ

૧. રામગઢ જીલ્લા : સક્ષમ પ્રાધિકારી અને પ્રાંતઅધિકારી (જમીન સંપાદન) રામગઢ, મેટ્રો સેંન્ટર નં - ૧ ઉરણ, રામગઢ, "સિડકો" નોડલ ઓફિસ. ઈજનેરી વિભાગ, દ્રોનાગિરી સેક્ટર _ ૧૪, બોકડવિરા, તાલુકા-ઉરન, રામગઢ.
૨. થાણે જીલ્લા : સક્ષમ પ્રાધિકારી અને પ્રાંતઅધિકારી (જમીન સંપાદન), પશ્ચિમ ફ્રેઈટ કોરીડોર સૂર્ય પ્રકલ્પ, ઈરાનીરોડ, આઈડીબીઆઈ બેંક સામે, દહાણુ, થાણે.
૩. વલસાડ જીલ્લા : સક્ષમ પ્રાધિકારી અને પ્રાંતઅધિકારી (ભુમિ સંપાદન અધિકારી), બીજોમાળ, જીલ્લા સેવા સદન -૨, કલેક્ટર ઓફિસ, વલસાડ.
૪. નવસારી જીલ્લાઃ સક્ષમ અધિકારી અને ડેપ્યૂટી કલેક્ટર, નવસારી, જુના થાણા, બહુમાળી મકાન, બ્લોક નંબર-C, પહેલા માળે, નવસારી.
૫. સૂરત જીલ્લા : સક્ષમ પ્રાધિકારી અને વિશેષ ભુમિ સંપાદન અધિકારી, શાખા નં - ૪, પાંચમામાળે, "એ" બ્લોક, બહુમાળી ભવન, સુરત.
૬. ભરૂચ જીલ્લા : સક્ષમ પ્રાધિકારી અને વિશેષ ભુમિ સંપાદન અધિકારી, જમીન સંપાદન શાખા ભરૂચ, કલેક્ટર ઓફિસ, ભરૂચ.
૭. વડોદરા જીલ્લા : વિશેષ ભુમિ સંપાદન અધિકારી ઉનીટ નં. ૧, રૂમ નં. ૬૧૫, છઠોમાળ, કુબેર ભવન, જમીન સંપાદન શાખા, કોઠી કોમ્પલેક્ષ, વડોદરા.
૮. રેવારી જીલ્લા : જીલ્લા રેવેન્યુ અધિકારી(ડિ.આર.ઓ.), ડી.સી. ઓફિસ, છોટા સચિવાલય, રેવારી.
૯. અલવર જીલ્લા : સબ ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ(એસ.ડી.એમ)/એસ.ડી.ઓ, એસ.ડી.એમ/તીજારા, તાલુકા - તીજારા, અલવર.
૧૦. મેવાળ જીલ્લા : જીલ્લા રેવેન્યુ અધિકારી(ડિ.આર.ઓ.),ડી.સી. ઓફિસ, જીલ્લા સચિવાલસ નુહ, મેવાડ.
૧૧. ગુડગાંવ જીલ્લા : જીલ્લા રેવેન્યુ અધિકારી(ડિ.આર.ઓ.),ડી.સી. ઓફિસ, છોટા સચિવાલય, ગુડગાંવ.
૧૨. પલવલ જીલ્લા : ઉપ ખંડ મેજીસ્ટ્રેટ(એસ.ડી.એમ.), એસ.ડી.એમ ઓફિસ, પલવર.
૧૩. ફરીદાબાદ જીલ્લા : જીલ્લા રેવેન્યુ અધિકારી(ડિ.આર.ઓ.), છોટા સચિવાલય, સેક્ટર _ ૧૨, ફરીદાબાદ.
૧૪. ગૌતમ બુધ્ધ નગર : ઉપ ખંડ મેજીસ્ટ્રેટ એસ.ડી.એમ.(સરદાર), ડી.એમ ઓફિસ, ગૌતમ બુધ્ધ નગર.

સેમુ (SEMU), DFCCIL, Head Office, પ્રગતિ મેદાન, મેટ્રો સ્ટેશન બિલ્ડીંગ, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૦૧